स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–25, अंक–11
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2074, नवंबर 2017

संपादक
अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अनुक्रम

आवरण कथा – पृष्ठ–6

स्वदेशी महारैली

स्वदेशी संवाद

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

13 मुद्दा
जीएसटी के दर्द से छोटों को बचाने की कवायद
..... डॉ. अश्वनी महाजन

15 ज्वलंत मुद्दा
विश्व भूख सूचकांक, भारत व स्वदेशी की रीति–नीति
..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

20 आर्थिकी
चौराहे पर विश्व–व्यवस्था
..... दुलीचन्द रमन

22 विचार
एच1बी वीजा पर साहस दिखाइए!
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

24 कृषि
किसानों में कुपोषण की कुंजी
..... देविंदर शर्मा

26 जीएम फसलें
जीएम सरसों का खतरा टलने से राहत
..... भारत डोगरा

28 विमर्श
वामपंथ से कोसो दूर देशभक्ति
..... आशीष रावत

30 शिक्षा
भारतीयता के अनुरूप हो शिक्षा व्यवस्था
..... डॉ. रेखा भट्ट

32 सेहत
कैंसर से जंग की नई उम्मीदें
..... निरंकार सिंह

पाठकनामा

स्वदेशी महारैली

भारत अब और अधिक विदेशी (चीनी) वस्तुओं को बर्दास्त नहीं करेगा। गत 29 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के रामलीला मैदान में स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर 'स्वदेशी महारैली' में जुटी भारी भीड़ का मनसूबा साफ–साफ दिख रहा था कि अब लोग चीन से आर–पार नहीं बल्कि पार–पार की बात देखना चाहते हैं। देश में जिन लोगों के दिमाग में भी चीनी वस्तुओं के सस्ता होने का भ्रम था, रैली में जुटी भीड़ से वह ठहता नजर आया।

चीनी मंसूबे ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए दिख रहे हैं। 2015–16 व 2016–17 के भारत चीन व्यापार आंकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट पता चलता है कि चीन की चमक उतरने लगी है। चीन भी इसे लेकर चौकस हो गया है। उसे भी पता है कि अगर भारत का विशाल बाजार उसके हाथ से फिसला तो दुनिया की जमीन पर नजर गडाने वाले के खुद के पैरों के नीचे की जमीन नहीं बचेगी।

चीन को संभालना चीनी हुकमरानों के लिए बड़ा भारी सौदा साबित हो जायेगा, क्योंकि चीन यह भली–भांति जानता है कि उसकी सारी आर्थिकी भारतीय बाजार पर टिकी है। अगर भारत का बाजार उसे छोड़ दें तो फिर वह कहीं का नहीं बचेगा। यहीं कारण है कि बिना आगे–पीछे देखें चीन चुपके से डोकलाम से बोरिया–बिस्तर उठाकर भाग खड़ा हुआ, हाफिज सईद पर उसके सुर बदल गये, वन बेल्ट–वन रोड़ पर दुनिया भर में घुम–घुमकर सफाई दे रहा है। इन सबके लिए हमें स्वदेशी जागरण मंच को धन्यवाद देना चाहिए, जिनने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के नाम पर देश को लामबंद किया। आज देश में चीन के खिलाफ एक संयुक्त रोष एकत्रित हुआ है। अगर इसकी तासीर ऐसी ही बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब चीन अपने बड़बोलेपन से बाज आयेगा और भारत की प्रभुत्ता को नजदअंदाज नहीं कर पायेगा।

मनोज कुलियाल, *उत्तराखंड*

✽✽✽✽✽

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

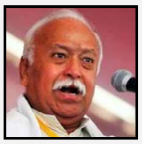

समाज में विषमता खत्म होने तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

डॉ. मोहन भागवत
आरएसएस प्रमुख

जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक ले जाने वाला कदम है। सरकार चाहती है कि इसका लाभ आमजन तक पहुंचे।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

भारत में 'इज आफ डूइंग बिजनेस' का माहौल अच्छा होने के नाते दुनिया भर में सकारात्मक माहौल बना है। हमारी रैंकिंग भी सुधरी है।

सुरेश प्रभु
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

जिन गैसों का प्रयोग हिटलर अपने विरोधियों को मारने के लिए निर्मित गैस चैंबर में करता था, हम अब वैसे ही रसायनों का उपयोग सरेआम खेतों में कर रहे हैं और अपने किसानों की मौत का आमंत्रण दे रहे हैं।

किशोर तिवारी
कृषक हितैषी

संपादकीय

डब्ल्यूटीओ में राष्ट्रीय हितों की रक्षा

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 11वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 10 से 13 दिसंबर, 2017 के बीच आयोजित होना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक निहितार्थ वाले विषयों, मसलन खाद्य सुरक्षा और आजीविका के संभावित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे कार्यक्रम में शामिल हैं। कृषि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आबादी का अधिकांश हिस्सा इससे सीधे जुड़ा है। विकसित देशों द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी, विशेष रूप से एएमएस (समर्थन का समग्र उपाय) की व्यवस्था कर भारत जैसे देश के किसानों को चोट पहुंचा रही है। ए.एम.एस. को खत्म करने के लिए भारत ने प्रस्ताव दिया है, और इसे आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है। विकास सब्सिडी, जो हमें मिलती है, को छुआ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये विकासशील देशों के किसानों के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण हैं। 100 से अधिक विकासशील देश इस प्रयास का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया के अरबों छोटे किसानों के समर्थन से भारत विश्व व्यापार संगठन में एक अच्छा माहौल बना सकता है।

दूसरा भारत को सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान के लिए तत्काल दबाव डालना चाहिए, जिसे बिना किसी सीमा के अनुमति दी जानी चाहिए। 'पीस क्लॉज़' के तहत मुश्किल शर्तों के अनुपालन को अब भारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य करने में बाधा खड़ी होती हैं। इस तरह का निर्णय लिए जाने पर सहमति बनी हैं।

मंत्रीस्तरीय बैठक में मत्स्य पालन सब्सिडी पर नियमों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। सतत् मछली पकड़ने की रक्षा की जानी चाहिए और बड़े औद्योगिक मछली पकड़ने वालों पर अंकुश लगाने की बात होनी चाहिए। चिंताजनक बात यह है कि वर्तमान प्रस्तावों पर विचार–विमर्श केवल विकसित देशों के संदर्भ में किया जा रहा हैं। वास्तव में विकासशील देशों को अपनी सब्सिडी जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। वास्तव में हमारे मतस्य पालन में संलग्न मछुआरों को विशेष सहायता की तत्काल जरूरत है, जो वर्तमान प्रावधान में नहीं हैं। स्वदेशी जागरण मंच देश के मछुवारों की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ता रहा हैं। मंच गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से होने वाले मछुआरों के जीवन और आजीविका की चिंता करता रहा हैं। इस पर गहन शोध की जरुरत हैं। बिना विचार विमर्श के सुधार की कोशिश के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करना बेहतर है। इस तरह की चर्चा बाद में की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा निवेश की सुविधा के जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता का विषय हैं, क्योंकि पूर्व का इतिहास हैं कि जब किसी देश को इनके द्वारा निवेश का लाभ दिया गया, वह निवेशक के संरक्षण और बाजार की दृष्टि से जो कुछ शर्ते लगाई गई वह परेशानी का बड़ा कारण बना। भारत को इसका भारी खामियाज़ा भुगतना पड़ा। निवेश पर बहुपक्षीय मंच से एक अतिरिक्त प्रतिबद्धता देना, इस समय में एक बड़ी गलती होगी। भारत को निवेश पर किसी भी वार्ता को पूरी तरह से खारिज करने की अपनी स्थिति का पालन करना चाहिए, जैसा कि इस साल जिनेवा में किया।

अंत में, ई–कॉमर्स एक जटिल और अज्ञात क्षेत्र है, जहां देश का भविष्य प्रभावित हो सकता है। ई–कॉमर्स के वार्ता में शामिल होने से भविष्य की आर्थिक नीति बनाने और विशाल ई–कॉमर्स कंपनियों को विनियमित करने की सरकार की क्षमता समाप्त हो जायेगी। भारत को 'डाटा' जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों को मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। साथ ही भारत को विश्व व्यापार संगठन को स्वस्थ, कृषि और वित्त जैसे क्षेत्रों की नीतियों को आकार देने वाले नियमों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ई–कॉमर्स से आने वाले टैरिफ राजस्व का नुकसान और आयात पर विनियामक नियंत्रण दोनों ही मामले भारत जैसे विकासशील देश के लिए अकल्पनीय हैं। क्योंकि इससे भारी नुकसान की संभावनायें हैं। ऐसे में भविष्य की ई तकनीक किस प्रकार विकसित होगी और किस प्रकार के नियमन की आवश्यकता होगी, यह अभी तय नहीं हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को नियामक मुक्त करने का सवाल इस समय भी नहीं उठना चाहिए। आशा की जा रही है कि भारत सरकार इन मुद्दों पर सही रूख अपनायेगी। भारत को किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है।

स्वदेशी महारैली

'स्वदेशी स्वीकार-चायनीज़ बहिष्कार' का एक सफल अभियान

चीन व चीनी वस्तुओं के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने सिंहनाद कर दिया है। बात–बात पर भारत को आंख दिखाने व भारतीय बाजार पर अपना सिक्का जमाने की चीन की चालाक चालों से देश की जनता को आगाह करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने चीन निर्मित सभी वस्तुओं व सेवाओं के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में गत 29 अक्टूबर 2017 को आयोजित 'स्वदेशी महारैली' के दौरान मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरूण ओझा व मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने चीन के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए कहा कि भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए मंच की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक की भारतीय बाजार व भारतीय उपभोक्ताओं को चायनीज़ वस्तुओं के चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं करा लिया जाता। डॉ. महाजन ने बताया कि मंच अपनी तरफ से भारतीय बाजार का एक अध्ययन कर अपना प्रपत्र सरकार को आने वाले दिनों में सौंपेगा तथा चीन के आयात से हो रहे नुकसान को रेखांकित कर बचाव के उपाय पर अमल करेगा।

'स्वदेशी स्वीकार–चायनीज़ बहिष्कार' के बैनर तले देश से कोने–कोने से आये लाखों लोगों के हुजुम ने यह साबित कर दिया कि चीन के प्रति देश के लोगों में न सिर्फ गुस्सा है बल्कि अब वे आर–पार की बात भी करते हैं। उमड़े जनसैलाब ने चीन को यह संदेश दिया कि भारतीय लोगों में चीनी वस्तुओं/सेवाओं के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही उनके सस्ते और गुणवता का कोई आकर्षण है। भीड़ ने देश के उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है, जिनका यह मानना रहा है कि चूंकि चायनीज़ वस्तुएं बहुत सस्ती हैं, इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद बनी हुई है।

लगभग 6 घंटे तक की मैराथन महारैली में संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री इंद्रेश कुमार, श्री आचार्य येशे पुश्तोक (तिब्बती संसद में उपसभापति), जनरल जी.डी. बक्शी (कारगिल युद्ध के नायक), श्री अरूण ओझा (राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच), श्री दिनेश कुलकर्णी (सांगठनिक सचिव, भारतीय किसान संघ), श्री प्रभाकर केलकर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसान संघ), श्री पवन कुमार (मंडल सचिव, भारतीय मजदूर संघ), श्री जितेन्द्र गुप्ता (राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष, लघु उद्योग भारती), श्री श्रीनिवास (राष्ट्रीय उप संगठन सचिव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद), श्री युद्धवीर सिंह (राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत)), श्री श्यामबिहारी मिश्रा (अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल) आदि के अलावा भारी संख्या में किसान नेता, मजदूर नेता व सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर संघर्षरत नामचीन बुद्धिजीवियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से चीनी वस्तुओं व सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया तथा सरकार से यह मांग की कि सरकार को चीनी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक कड़े कदम

घोषणा–पत्र

स्वदेशी सुरक्षा अभियान के क्रम में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आहूत इस महारैली में आये हुए समस्त स्वदेशी प्रेमी बंधु, भगिनिओं को अभिनन्दन। विशेषतः गत दो वर्ष में जिस प्रकार पूरा भारतीय जन समाज, चीनी वस्तु विरोधी अभियान जारी रखे हुए है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। फलतः देश में अनेक चीनी वस्तुएं, विशेषकर चीनी पटाखा, खिलौने, लाइट–लड़ियां, छोटे इलैक्ट्रानिक्स उपकरण, कंबल, ताला, बच्चों की साइकिल से प्रारंभ कर चीन निर्मित मोबाइल तक के बाजार में बिक्री के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव के साथ–साथ इन सभी उत्पादन क्षेत्रों में भारतीय उद्योग धीरे–धीरे पुनःस्थापित हो रहे हैं। किंतु बंधुओं, जिस प्रकार से चीनी वस्तुओं ने भारतीय तथा विश्व बाजार को ग्रसित किया है, इससे उभरने के लिए ये लड़ाई हमको बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। साथ–साथ विश्व में चीन का आक्रमणकारी, विस्तारवादी कार्य बढ़ रहा है, उसको भी परास्त करने का समय आ चुका है। चीन में मानवाधिकार उल्लंघन की अब तक की जितनी घटनाएं प्रकाश में आई है उनसे यह स्पष्ट होता है कि चीन में खुलेआम मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्वदेशी जागरण मंच की संवेदना चीनी जनता के साथ है। हमारा नैतिक समर्थन चीनी जनता के साथ है। हम इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनवासियों की आवाज को बुलंद करने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करते है कि वह भी चीन में हो रहे इन मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए तत्पर रहें।

भारतीय सीमा में चीनी सेना का बार–बार घुसपैठ एवं सैन्य गतिविधि के कारण भारतीय सीमा आज असुरक्षित है। जिस प्रकार पाकिस्तान को अस्त्र–शस्त्र एवं आर्थिक सहायता देना एवं पाकिस्तानी आतंकवादी कार्य को चीन द्वारा समर्थन करना, भारत की सुरक्षा के प्रति संकट की गंभीरता प्रकट करता है। इसीलिए आज भारतीय समाज के अंदर चीन के प्रति आक्रोश निर्माण हुआ है। परंतु समाज उस आक्रोश को कार्य में परिणत करने के लिए संकल्पित होकर समस्त चीनी वस्तुओं को निजी जीवन की आवश्यकता से निकालकर फेंकना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षण चीनी वस्तु बहिष्कार को गति देने के लिए आगे आना पड़ेगा। मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे मौहल्ले से, मेरे गांव/नगर से, सर्वोपरि मेरा देश भारतवर्ष के बाजार से संपूर्ण चीनी वस्तुओं तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, इस दिशा में समाज को तथा हमारे कार्यकर्ताओं को काम में लगना होगा। देशभर में एक उग्र जन–जागरण निर्माण करना पड़ेगा। आएं, हम सब मिलकर यह कार्य करें।

समाज में जिस प्रकार चीनी वस्तु तथा चीन की आक्रमणकारी मानसिकता के विरोध में जन भावना का निर्माण हुआ है, उसे सरकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार समाज से बाहर नहीं है। विगत कुछ दिनों में सरकार द्वारा लिये जाने वाले कुछ कदम, जैसे–चीनी वस्तुओं के ऊपर एंटी डंपिंग डयूटी (Anti Dumping Duty) लगाना, चीनी निर्मित प्लास्टिक वस्तुओं के ऊपर गुणात्मक मापदंड (Qualitative Measures) लगाना, OBOR का भारत सरकार के द्वारा बहिष्कार करना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पटल पर डोकलाम घटनाचक्र में चीन को अलग–थलग करना इत्यादि साहसिक एवं उदाहरणीय कदम हैं। परंतु जिस प्रकार नागपुर मैट्रो का 960 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट, चेन्नई–बंगलूरू–मैसूर हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट से प्रारंभ करके अनेक थर्मल पावर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा अनेक भित्ती–भूमि विकास के कार्य का टेंडर चीनी कंपनियों को देने के साथ–साथ चीनी एफडीआई को आमंत्रित करना इत्यादि कार्य को समाज सहजता से स्वीकार नहीं कर रहा है। इसीलिए सरकार के सामने ये सारे टेंडर निरस्त करना एवं चीनी निवेश का बहिष्कार करने का समय आ चुका है।

जिस प्रकार 63 लाख वर्ग किमी. वाला चीन 1951 से 1990 के बीच 93 लाख वर्ग किमी. वाला चीन कैसे बना, वो सारा विश्व जानता है। तिब्बत को अख्तियार करने के साथ–साथ भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, जापान आदि और भी कई देशों की कुछ–कुछ भूमि आज चीन के कब्जे में है। चीन अत्यन्त मंहगें दर पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों को ऋण उपलब्ध कराकर वहां की भूमि हड़पना व सरकारों को स्थिर व अस्थिर करने जैसा घृणित कार्य कर रहा है। हमें अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ौसी देशों को गुमराह होने से बचाने के लिए तत्पर एवं सावधान रहने की जरूरत है। आतंकवाद की कोख पाकिस्तान व एकछत्रवादी उत्तर कोरिया को चीन जिस हद तक समर्थन दे रहा है, वह विश्व मानव समाज के लिए एक काल रात्रि का आमंत्रण सदृश्य है। इसीलिए संपूर्ण विश्व को चीन के साम्राज्यवादी, आक्रमणकारी, युद्धखोर, अहंकारी, मनोभाव का उचित जवाब देने के लिए, चीन की आर्थिक ताकत को तोड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। विश्व समाज चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के साथ–साथ चीन को वैश्विक मंच पर अलग–थलग करने की आवश्यकता है। तिब्बत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना संपूर्ण विश्व का कर्तव्य है। फलतः चीन का अहंकार समाप्त होने के साथ–साथ आगामी विपत्ति से विश्व बच जायेगा। हमारा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सपना तभी साकार होगा। **भारत माता की जय। जय स्वदेशी।**

उठाने चाहिए, ताकि देशी व्यापार एवं व्यापारियों की रक्षा–सुरक्षा की जा सके।

मालूम हो कि स्वदेशी जागरण मंच पिछले एक साल से वैश्वीकरण के खिलाफ देश के लोगों को लामबंद करने के लिए 'राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान' चलाये हुए है। अभियान के दौरान मंच के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में बैठक, जन–संवाद, विचार गोष्ठी, धरना–प्रदर्शन आदि आयोजित कर इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता फैलाने का वृहद कार्यक्रम चलाया। मंच के

माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

स्वदेशी महारैली, 29 अक्टूबर 2017, रामलीला मैदान, के समापन पर प्रस्तुत ज्ञापन

माननीय **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,**

भारतीय हितों की सुरक्षा हेतु चीनी आयातों, चीनी निवेश और चीनी कंपनियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के परियोजनाओं में भाग लेने हेतु रोकने के लिए प्रभावी कदम उठने की जरूरत।

जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारा देश चीन से मशीनरी, इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रिकल और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं, टायरों, परियोजना वस्तुओं आदि के भारी आयात व उसके फलस्वरूप होने वाले व्यापार घाटे के कारण भयंकर संकट से गुजर रहा है। हमारे छोटे–बड़े उद्योग धंधे ही बंद नहीं हुए, बड़ी संख्या में हमारा युवा भी उसके कारण बेरोजगार होता जा रहा है। वर्ष 2016–17 में चीन से हमारा व्यापार घाटा 51.1 अरब डालर (3 लाख 30 हजार करोड़ रूपये) तक पहुंच चुका था, जो हमारे कुल व्यापार घाटे (106. 2 अरब डालर) का 48 प्रतिशत था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पता चलता है कि चीन से भारी आयातों के कारण देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भारी नुकसान और चीन के कुकृत्यों से चिंतित जनता द्वारा देश के कोने–कोने में चीनी माल के बहिष्कार के कारण चीन से आने वाले उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार 50 प्रतिशत घट गया है और चीन से हमारा व्यापार घाटा पिछले एक साल में 2 अरब डालर घटा है। इसके फलस्वरूप देश के कई हिस्सों जैसे पानीपत (हरियाणा), मोरबी (गुजरात) इत्यादि में बंद पड़े उद्योगों को एक नया जीवनदान मिला है।

हमारे देश से व्यापार द्वारा भारी लाभ उठाने के बावजूद भी चीन भारत से लगातार शत्रुता का भाव रखता आया है। पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे वाले भारत के भू–भाग में सैनिक अड्डे बनाने का काम हो, भारतीय सीमा का अतिक्रमण हो, कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में अड़ंगा डालना हो, भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एन.एस.जी.) में सदस्यता की बात हो, भारत के कई भू–भागों पर अपना अधिकार जताते हुए, भारत को बार–बार परेशान करने की चाल हो, चीन के कुकृत्यों की एक लंबी सूची है। भारत के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न करने के अलावा पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरिडोर (सीपीईसी), वन बेल्ट वन रोड़ (आबीओआर) इत्यादि के माध्यम से चीन अपने नापाक एवं विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी उपाय अपनाते हुए इन मंसूबों को सफल न होने दे।

धोखे से सामान को सस्ता कर के भारतीय उद्योगों को पहले प्रतिस्पर्द्धा से बाहर किया और बाद में भारतीय उद्योगों को कच्चे माल और लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भर बना दिया। चीन पर भारी निर्भरता के कारण अब उसने कीमतें बढ़ाकर भारतीय बाजारों में शोषण शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, पिछले काफी समय से दवा उद्योग में चीन से आने वाले सस्ते कच्चे माल (एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिऐट्स यानि एपीआई) के आयात के चलते भारत का एपीआई उद्योग काफी हद तक नष्ट हो गया। अब भारतीय दवा उद्योग की चीन पर निर्भरता का लाभ उठाते हुए चीन ने फॉलिक एसिड (विटामिन बी कांप्लेक्स के लिए रसायन) की कीमत 10 गुणा बढ़ा दी है। इसके साथ एंटी बायोटिक दवाईयों में एमोक्सी साईक्लिन रसायन की कीमत 2 गुणा कर दी गई है। यानि चीन अब हमारे दवा उद्योग का शोषण करने लगा है।

स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार द्वारा चीनी आयातों को रोकने संबंधी प्रयासों जैसे 94 वस्तुओं पर एंटी–डंपिंग ड्यूटी लगाने, प्लास्टिक वस्तुओं, पावर प्लांटों आदि पर मानक लागू कर चीन से इन वस्तुओं के आयात पर रोक एवं चीन से आने वाली अन्य वस्तुओं के संबंध में मानक बनाकर उसे लागू करने, चीनी कंपनियों से प्रतिदान (रैसीप्रोसिटी) के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर प्रभावी रोक लगाने की प्रशंसा करता है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन करते हुए भारत में बने सामान को सरकारी खरीद में कीमत एवं मात्रात्मक प्राथमिकता देने संबंधी फैसले का भी स्वागत करता है।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार से मांग करता है कि:

1. आम वित्तीय नियम (जनरल फाइनांसिएल रूल्स) यानि जीएफआर में संशोधनों, जिनमें सरकारी खरीद में भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई है, घरेलू उत्पादन, विशेषतौर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं उनमें क्षमता निर्माण में मदद करने हेतु विशेष रियायतें दी जाएं ताकि वे घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम हो सके। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन से गैर बराबरी की प्रतिस्पर्धा के कारण हमारा घरेलू उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
2. जैसा कि यह एक स्थापित सत्य है कि चीनी माल घटिया होता है और उसके उत्पादों में जहरीले रसायन मिले होते हैं एवं उनके माल की कोई गारंटी भी नहीं होती, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार मानक (स्टैंडर्ड) बनाकर उनके घटिया माल को प्रतिबंधित करे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा मानक बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, इसलिए हमें द्रुत गति से इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।

3. चीन से रिज़नल कांप्रिहेंसिव इक्नॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) सहित किसी भी प्रकार का नया व्यापार समझौता न किया जाए।
4. अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर चीन देश के लिए तरह–तरह से मुश्किलें बढ़ा रहा है और केंद्र और राज्य सरकारें चीनी कंपनियों से कई प्रकार के निवेश समझौते कर रही हैं। वे यह कहने से भी हिचकिचा नहीं रही कि वे चीनी माल के आयात को तो सही नहीं मानती लेकिन चीनी निवेश का स्वागत करती हैं। कई राज्य सरकारों ने तो इस प्रकार के निवेश के लिए विविध सम्मेलन भी आयोजित किये हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और चीन से किसी भी प्रकार का निवेश समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
5. कई निजी कंपनियां भी चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में हमारा व्यापार और उद्योग चीनी कपंनियों के कब्जे में आता जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश चीनी कंपनियां चीनी सरकार के आधिपत्य में हैं, जिसके कारण युद्ध की स्थिति में हमारा समस्त व्यापार और उद्योग संकट में आ सकता है। भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश को प्रतिबंधित किया जाए।
6. चीनी कंपनियां बड़ी संख्या में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण ठिकानों, जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों, सीमा क्षेत्र आदि पर ठेके (कांट्रेक्ट) लेकर अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। इसके कारण देश की सुरक्षा को भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है। हालांकि सरकार द्वारा चीनी कंपनियों की भारत में निविदा (टेंडर) की प्रक्रिया में भागीदारी को रोकने हेतु प्रतिदान (रैसीप्रोसिटी) के आधार पर प्रक्रिया शुरू की है, जिसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ चीनी कंपनियों को रोकने हेतु सुरक्षा के खतरे के आधार पर भी कार्यवाही करने की सख्त है।
7. सरकार तिब्बत को चीनी शिकंजे से मुक्त करवा, उसकी संप्रभुता को बहाल करने हेतु पहल करें और उसके लिए आवश्यक कदम उठायें। भारत सरकार तिब्बती और चीनी लोगों के विरूद्ध मानव अधिकारों के हनन को रोकने हेतु विश्व में जागरूकता फैलाते हुए वैश्विक गठबंधन तैयार करें। इस संबंध में विश्व भर में वृहत समर्थन जुटाने हेतु अभियान शुरू किया जाये।
8. हालांकि हम जानते हैं कि सरकार पूर्व में हुए विश्व व्यापार संगठन के समझौतों एवं नियमों से बंधी हुई है, तो भी अभी भी कई मामलों में आयात शुल्क विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में दिए गए वचन से अभी भी बहुत नीचे हैं। इसलिए हम इन उत्पादों पर आसानी से शुल्क बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ चीन से भारी आयातों, भारी व्यापार घाटे और चीनी निवेशों के बढ़ते मकड़जाल के कारण होने वाले नुकसानों के संबंध में भी हमें अध्ययन करना होगा। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय में विशेष चीनी प्रकोष्ठों की रचना की जाए ताकि ठोस जानकारियों के आधार पर इन समस्याओं से निजात पाने हेतु प्रयास किए जा सकें।

डॉ. अश्वनी महाजन
समन्वय प्रमुख
राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान

सतीश कुमार
अभियान प्रमुख
राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान

रामलीला मैदान में स्वदेशी महारैली के अवसर पर उपस्थित एक लाख से अधिक जनमानस की ओर से

अधिकारियों ने चीनी वस्तुओं व सेवाओं को लेकर देश के नागरिकों की नब्ज टटोली तथा जनता के उत्साह को देखकर आंदोलन को गति दी।

वर्ष भर चले विशेष अभियान के दौरान लोगों को चीनी वस्तुओं के आयात से होने वाली असुविधाओं से परिचित कराया गया, वहीं मंच के अधिकारियों ने लघु–कुटीर व छोटे–मझौले उद्योगों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया। उद्योगों के समक्ष खड़ी चुनौतियों का अध्ययन कर सरकार से इनके समाधान की अपेक्षा भी की।

स्वदेशी जागरण मंच का साफ मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए तथा स्वदेशी व्यापार व उद्योगों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मंच के सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने बताया कि आज देश में 130 करोड़ लोग है, देश में 6.25 लाख गांव है, विश्व का सर्वोधिक पशुधन भारत के पास है, विश्व में सबसे अधिक खेती योग्य जमीन हमारे पास है, 127 तरह की विविध कृषि जलवायु क्षेत्र और 400 से अधिक प्रकार के संगठित लघु उद्योग संकुल व 7 हजार से अधिक असंगठित सूक्ष्म उद्योगों के संकुल हैं। इसी क्रम में देश में 3 करोड़ 10 लाख लघु व सूक्षम उद्यम है, जिसमें 7.5 करोड़ लोग रोजगार पाये हुए हैं और इन लघु उद्यमों के द्वारा 6 हजार से अधिक प्रकार के उत्पाद का कारोबार किया जाता है। इनमें से 1 करोड़ 24 लाख तो केवल ग्रामीण उद्यम है। डॉ. महाजन ने कहा कि इतने जबरदस्त उद्योग नेटवर्क के रहते अगर कोई विदेशी भारत के बाजार पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है तो यह सरकार की अदूरदर्शिता का द्योतक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसके प्रति गंभीरता से न सिर्फ सोचने लगी है, बल्कि स्वदेशी की लड़ाई बढ़–चढ़कर लड़ना चाहती है।

चीन के खिलाफ देश भर में चल रहे जागरूकता अभियान का असर रहा कि बीजिंग को डोकलाम मुद्दे पर अपने

पैर वापिस खीचने पड़ें। स्वदेशी जागरण मंच का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह का दबाव भारत सरकार ने डोकलाम मुद्दे पर चीन के समक्ष बनाया, उससे भी बड़ी रणनीतिक चाल तिब्बत की स्वायतत्ता व विदेशी वस्तुओं (खासकर चीन के बने सभी सामानों व सेवाओं) के लिए पहल करनी चाहिए। जिस तरह हाल के दिनों में चीन डोकलाम को लेकर उग्रता दिखा रहा था तथा भारत के विरोधी पाकिस्तान में पनाह पाये आतंकी हाफिज सईद की वकालत कर रहा था, उससे एक बार लगने लगा था कि अब भारत को आर–पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। भारत के लोगों ने चीन को सबक सिखाने की ठानी। चीनी सामानों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। आम जनता में चीन को लेकर एक सहमति बनी, जिसकी अनुगूंज जल्द ही चीन तक पहुंची और अपने पेट पर लात पड़ता देख चीन ने डोकलाम से अपने पैर खींच लिये।

एक अध्ययन में यह भी निकलकर आया है कि 2016–17 में चीन से आयात में भारी कमी आई है। कई एक वस्तुओं के आयात में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। दीपावली के मौके पर होने वाले आयात में 60 प्रतिशत तक की कटौती हुई है। बताते हैं कि एंटी डंपिंग डयूटी के चलते भी इसमें कमी आई है। स्टील के आयात में 2015–16 में 43 प्रतिशत की कमी हुई थी, जबकि 2016–17 में यह बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई। इसी तरह अजैविक रसायन, खाद और परियोजना वस्तुओं में भी 12 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की कमी आई है।

ज्ञातव्य हो कि स्वदेशी जागरण मंच पिछले 1 साल के दौरान चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर जो देशव्यापी जागरूकता अभियान 'राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान' चलाया था, उसमें देश के 1 करोड़ 30 लाख लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर हस्ताक्षर कराया था तथा इस बात के लिए सहमति बनाई थी कि पत्रक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति भविष्य में चीनी वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। मंच की यह पहल बहुत कारगर साबित हुई। उक्त 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस अभियान को अपने स्तर से और आगे बढ़ाया तथा चीनी सामानों से दूरी बनाने की अपील अपने–अपने समाज में की।

चीनी वस्तुओं व सेवाओं की गुणवता हमेशा से संदिग्ध रही है। इसे छिपाने के लिए चीनी कंपनियां दाम के स्तर पर दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करती रही हैं। अबकी पहली बार स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने घर–घर जाकर चीनी वस्तुओं के गुणवता पर आमने–सामने की बात की तथा लोगों को यह समझाने में सफलता मिली कि इसके प्रयोग से मानवीय जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। लोगों ने मंच की अपील को दोनों हाथों से स्वीकार किया, उन्हें लगा कि बात में दम है और जो चीज देश के लिए हानिकारक है, वह देश के नागरिकों के लिए किसी भी कीमत पर लाभदायक नहीं हो सकती।

मंच द्वारा आयोजित महारैली के दौरान वक्ताओं ने सरकार के समक्ष कई एक मांगें रखीं। इनमें भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने, देश में उद्योग के लिए उचित माहौल बनाने, चीन से आयत पर कड़े कानून बनाने के साथ–साथ भारत सरकार के वाणित्य व वित्त मंत्रालय के अधीन एक 'विशेष चीनी प्रकोष्ठ' बनाने की मांग की। मंच का मानना है कि अलग चीन प्रकोष्ठ बनाकर उसकी निगरानी की जानी चाहिए तथा चीनी वस्तुओं के भारतीय आवक से हमारे घरेलू बाजार पर पड़ने वाले विपरीत असर को चिन्हित कर उसका समाधान करने में सहूलियत होगी। मंच का यह भी कहना है कि भारत सरकार को तिब्बत (जिसका कि मुख्यालय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में स्थित है) की स्वायतत्ता के लिए भी अब खुलकर खड़े हो जाना चाहिए। मंच का स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दमदारी के साथ डोकलाम के मुद्दे पर चीन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उसी तरह की संजीदगी के साथ चीन वस्तुओं के बहिष्कार व तिब्बत के मुद्दे पर सीना तानकर खड़े होने चाहिए।

मंच की चीनी वस्तुओं के खिलाफ चल रही यह जंग आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी। योजना है कि आने वाले दिनों में मंच देश के कोने–कोने तक जाकर भारतीय उद्योगों का एक सर्वेक्षण करेगा तथा मौजूदा समय में उद्योगों के समक्ष खड़े संकट की शिनाख्त कर सरकार पर समाधान के लिए दबाव बनायेगा। ❑❑

स्वदेशी महारैली की कुछ झलकियां, कुछ उपलब्धियां

— सतीश कुमार —

- राष्ट्रीय स्वदेशी–सुरक्षा अभियान व स्वदेशी महारैली का प्रभाव तो देखिए कि अक्टूबर आते–आते राहुल गांधी भी बोले कि चायनीज़ माल के आयात के कारण हमारी नौकरियां खत्म हो रही है। मुलायम सिंह तो उससे भी पहले चायनीज़ आयात के बारे में बोल ही चुके हैं। अन्य राजनेता भी जो स्वदेशी या विचार–परिवार के किसी भी अभियान का विरोध ा करते ही हैं वे 'स्वदेशी स्वीकार–चायनीज़ बहिष्कार' मुद्दे पर या तो चुप रहे या स्वदेशी जागरण मंच के साथ रहें। जनता (हर वर्ग की) तो मंच के साथ थी ही, मुस्लिम, ईसाई या अन्य मतावलंबी भी इस मुद्दे पर खुलकर साथ आये।

- स्वदेशी महारैली की सबसे स्पष्ट (ठीक) व 3.3 मिनट की प्राईम न्यूज़ जानते हैं, किस टीवी चैनल में चलाई? व चलाई एनडीटीवी ने। जी हां, वहीं चैनल जिसे रवीश तिवारी ने 1. 5 साल पहले अपने प्राईम टाईम शो में बहस का विषय रखा था (दीपावली पर) – ''दीपावली पर चायनीज़ ही खरीदें''। आज तक ने so-sorry बनाया, तो Bol Bindass ने बहुत अच्छी कवरेज दी। सुदर्शन चैनल ने तो details करनी ही थी।
- राजस्थान की एक फिल्म इंडस्ट्री ग्रुप इसी मुद्दे पर फिल्म बना रहा है, वे अपनी पूरी टीम व साजो–सामान के साथ स्वदेशी महारैली में भी आयें। उनकी छोटी क्लिप तो बहुतों ने बनाई।

- जनरल जी.डी. बक्शी, मैनेजमेंट गुरू विवेक बिन्द्रा, प्रवचनकर्ता देवेन्द्र ठाकुर, जैन मुनि, सिनेमा कलाकार तारक मेहता आदि हर वर्ग ही लग गया स्वदेशी महारैली में ... 'चायनीज़ बहिष्कार–स्वदेशी स्वीकार' राष्ट्रीय मुद्दा बना। डोकलाम के बाद तो कवि, लेखक, अध्यापक, प्रोफेशनल, सभी की जुबान पर एक ही विषय रहा 'स्वदेशी स्वीकार–चायनीज़ बहिष्कार'।
- इतनी विशाल रैली, फिर भी न कोई धक्का मुक्की, न कोई परेशानी। न कोई भूखा गया, न प्यासा। हम अक्सर राजनैतिक

रैलियों में जाते हैं, अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं, पर हर बार कुछ–कुछ ऐसा जरूर होता है कि हम मन–तन से परेशान हो जाते हैं। परंतु पहली बार सब हंसते–खेलते वापिस आये, सब प्रसन्न रहें। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

'राष्ट्रीय स्वदेशी-सुरक्षा अभियान' व 'स्वदेशी महारैली' की मुख्य उपलब्धियां

सरकार द्वारा किये गये प्रयास

1. सरकार ने चीन से आयात होने वाले स्टील पर 18 प्रतिशत की Anty Dumping Duty लगाई है, जिसके कारण चीन का स्टील भारत के स्टील की तुलना में 6 प्रतिशत महंगा हो गया है। इसके फलस्वरूप चीन से स्टील आयात में 62 प्रतिशत की गिरावट आई है।
2. अभी 20 दिन पहले सरकार ने चीन से आने वाले बस और ट्रक के टायरों पर 23 प्रतिशत की Anty Dumping Duty लगाई है। एक अनुमान के अनुसार इससे इन टायरों के आयात में 70 प्रतिशत की गिरावट संभावित है।
3. चीन से आयात होने वाले पटाखों को Explosive Act का प्रयोग करते हुए पूरी तरह रोक दिया गया है। इससे शिवाकाशी सहित देश का पटाखा उद्योग चल पड़ा है तथा हजारों नये रोजगार का सृजन हो रहा है।
4. सरकारी खरीद में स्वदेशी माल को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम (General Finance Rules) में प्रावधान जोड़ा है कि 50 लाख तक की खरीद अब केवल 'Make in India' के तहत होगी अर्थात् चायनीज़ कंपनियां सरकारी खरीद से बाहर हो जायेगी।
5. चीन से आयात होने वाले प्लास्टिक के 14 प्रकारों पर पूरी तरह रोक लगी है। इसके फलस्वरूप खिलौना उद्योग आगे जाकर चल निकलेगा।
6. चीन से पावर प्लांटस का भारी आयातित क्षेत्र था। चीन की ओर से व्यापार संधि का तकनीकी रूप से उल्लंघन किये जाने को वजह बनाते हुए भारत ने भी चीनी पावर प्लांटस के पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं ग्रिड पर रोक लगा दी है।
7. रेलवे में ठेके दिए जाने को लेकर सुरक्षा मानक सहित अन्य मानक सरकार ने निश्चित कर दिए है। इस कारण चीनी कंपनियों को यह ठेके मिलने की संभावना घट गई है।
8. पिछले 14 वर्षों से चीन से व्यापार घाटा हर वर्ष बढ़ रहा था। वह पहली बार न केवल रूका है, अपितु 2 बिलियन डालर घटा भी है।
9. डोकलाम विवाद के बाद चीनी मोबाईल कंपनियों की बिक्री (ओप्पो तथा वीवो) 30 प्रतिशत तक गिरी है। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर उसने अपने 400 कर्मचारियों को वापस चीन भेजा है, अपितु अपने विज्ञापनों में बेतहाशा वृद्धि भी कर दी।
10. मकराना की टाईलों व पत्थर उद्योग सरकार द्वारा आयात नियम कड़े करने के कारण बढ़ रहा है।
11. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी S&P ने चीनी की वित्तीय स्थिति को AA+ से घटाकर कर A+ दिया है।
12. देश में मेन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के संकेत आ रहे हैं।
13. अब तक 112 वस्तुओं पर Anty Dumping Duty लगाई जा चुकी है।

समाज द्वारा किये गये प्रयास

1. पानीपत के युवा उद्यमियों ने बाहर से कंबल बनाने वाली आधुनिकतम मशीनें मंगवाई। देशी कारीगरों ने उन मशीनों को देखकर वैसी ही मशीनें यहां तैयार कर ली। लगभग 40 नई फैक्टरियां पानीपत में लगी, इससे हजारों लोगों को नया रोजगार मिल गया। कंबल, दरी, चादर का चीन से आयात 80 प्रतिशत घट गया।
2. इसी प्रकार देहरादून का लड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, आगरा का जूता उद्योग खड़ा हो रहा है।
3. समाज में चीनी माल के प्रति वितृष्णा बढ़ रही है। दिल्ली में द्वारका की एक रामलीला ने ओप्पो का 15 लाख रूपये का विज्ञापन ठुकरा दिया। ऐसे समाचार बहुत स्थानों से आ रहे हैं, जहां स्थानीय स्तरों पर कार्यक्रमों में विदेशी विज्ञापन ठुकराये गये हैं।
4. Assochem, Delhi ने भारत भर के सर्वेक्षण में पाया कि इस दीपावली में 40–45 प्रतिशत तक चायनीज़ वस्तुओं की बिक्री में गिरावट आयेगी।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किये गये कार्यक्रम

1. चीनी चुनौती के विभिन्न आयामों (व्यापार घाटा, रोजगार को खतरा, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, पर्यावरण, चीन भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए निकला) को समाज के ध्यान में लाने हेतु थिंक टैंक का गठन व अनके कार्यक्रम।
2. 10 भाषाओं में 8 लाख पुस्तिकाएं, 3 करोड़ से अधिक पत्रकों का प्रकाशन व वितरण हुआ।
3. 1 करोड़ से अधिक नागरिकों के द्वारा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर।
4. सोशल मीडिया प्रचार–डाक्यूमेंट्री आदि का निर्माण, रामलीलाओं में प्रचार, समाचार पत्रों में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम प्रकाशित हुए।
5. वक्ता प्रशिक्षण वर्ग द्वारा हजारों वक्ताओं का प्रशिक्षण।
6. स्वदेशी महारैली में एक लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना।
7. चीनी मीडिया व सरकार तथा विश्व के समाचार पत्रों के द्वारा अभियान को संज्ञान में लिया जाना। ❑❑

जीएसटी के दर्द से छोटों को बचाने की कवायद

9–10 नवंबर को संपन्न जीएसटी काउंसिल में कई अहम फैसले लेते हुए छोटे व्यापारियों, रेस्टोरेंट का काम करने वाले और लघु उद्यमों को राहत देने वाले कई फैसले लिए गये हैं। इससे पहले इस बैठक के लिए मंत्रीस्तरीय समिति ने इस बाबत कई सिफारिशें भी की थी। हालांकि विपक्षी दल इन बदलावों को गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कारण चाहे कोई भी रहा हो, 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में से 178 वस्तुओं को हटा लिया गया है और अब इस स्लैब में मात्र 50 वस्तुएं ही बची हैं। कई वस्तुओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

काम्पोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ की गई है और सभी श्रेणियों मेन्यूफैक्चरिंग, व्यापार और रेस्टोरेंट, काम्पोजिशन टैक्स की दर एकसमान मात्र 1 प्रतिशत ही रखी गई है। सभी रेस्टोरेंट पर कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इन प्रस्तावों से केंद्र को 60,000 करोड़ रूपये और राज्यों को 30,000 करोड़ रूपये का नुकसान होगा।

केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि लघु उद्यमियों द्वारा दिए गए करों का कुछ हिस्सा उन्हें वापिस किया जाए। ऐसा लगता है कि इन फैसलों से लघु उद्यमियों का जीएसटी दर्द पहले से काफी कम हो जाएगा।
– डॉ. अश्वनी महाजन

जीएसटी को एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देखा जा रहा था। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी समेत कई किस्म के अप्रत्यक्ष करों के बदले एकमात्र कर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया और उसे 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी जीएसटी के कारण होने वाले नुकसानों पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर कर रही है, लेकिन वास्तव में जीएसटी लागू करने संबंधी शुरूआत कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय ही हुई थी। कांग्रेस के जमाने के वित्त मंत्री हों या वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री सभी जीएसटी के पक्ष में अनेकों दलीले देते रहे हैं। इस बावत सबसे बड़ी दलील यह है कि पूरे देश में एक वस्तु पर कर की दर एक ही रहेगी। इसलिए न तो कोई असमंजस रहेगा और न ही विभिन्न राज्यों में अलग–अलग कर की दर होने से कोई विसंगति पैदा होगी। दूसरी बड़ी दलीज यह रखी गई कि लगभग सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो जाएंगे, इससे अलग–अलग पड़ावों पर कर लगने के कारण कीमतों में होने वाली बेजा वृद्धि, जिसे केसकेडिंग प्रभाव कहा जाता है, से भी बचा जा सकेगा।

क्या है जीएसटी?

वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढ़ांचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर तरह–तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते रहे हैं। संविधान में

केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और कुछ स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास था। उसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही थी। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष सभी प्रकारों के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो गए हैं।

छोटों का दर्द

हालांकि जीएसटी को एक सरल कर प्रणाली के नाते प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन छोटे व्यापारी और लघु उद्योग वाले इसे अत्यंत पेचीदा कर प्रणाली मान रहे हैं। आसान इसलिए कहा गया था कि सभी टैक्सों के बदले में एक ही टैक्स देना पड़ेगा और फायदेमंद इसलिए कहा गया कि किसी भी व्यापारी अथवा उत्पादक को उससे पूर्व के दौर में दिए गए तमाम टैक्स कर क्रेडिट मिल जाएगा और उसे केवल मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिड) पर ही कर देना पड़ेगा। कम्प्यूटर के द्वारा जीएसटी के बने नेटवर्क (जीएसटीएन) पर टैक्स रिटर्न भरकर पिछले समय में दिए गए करों का क्रेडिट भी मिल सकेगा। लेकिन लघु उद्यमी और छोटे व्यापारी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि बड़ी–बड़ी कंपनियों के लिए यह सिस्टम बहुत आसान है, लेकिन लघु उद्योगों के लिए यह भारी घाटे का सौदा है। उनकी पहली शिकायत यह है कि इस कर प्रणाली के अंतर्गत उन्हें तमाम प्रकार के कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसके कारण खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इस बावत उनका कहना है कि चार्टट एकाउंटेंट लोगों ने जीएसटी की पेंचीदगीयों के कारण अपनी फीस खासी बढ़ा ली है। उनका यह भी कहना है कि बड़े उद्योगों में सौदे बड़े–बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स पेड बिल मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। बड़े व्यवसायों में आसानी से टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। लेकिन छोटे उद्योगों के लिए यह इतना आसान नहीं होता। बिक्री करने पर टैक्स सरकारी खाते में जमा करना पड़ता है, जबकि टैक्स क्रेडिट मिलने में महीनों लग जाते हैं। इसके कारण उनकी पूंजी लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती है।

लघु उद्योगों की यह भी शिकायत थी कि जहां लघु उद्योगों को पूर्व प्रणाली में 1.5 करोड़ रूपए तक के उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क में छूट का प्रावधान था, अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं बचा। छोटों के लिए मात्र एक ही प्रावधान शुरूआती जीएसटी में था कि 75 लाख रूपए तक वे कम्पोजिट स्कीम में पंजीकृत होकर एक निश्चित दर पर टैक्स दे सकते हैं। इस स्कीम की सीमा डेढ करोड़ की उत्पाद शुल्क में सीमा से आधी ही थी। इसके आलावा 20 लाख सालाना से कम का व्यवसाय करने वाले छोटे उद्यमियों को जीएसटी में पंजीकरण से छूट थी। हाल ही में हुए परिवर्तनों से यह शिकायत काफी कम हो जायेगी।

जीएसटी के आलोचकों का कहना है कि जीएसटी के कारण छोटे व्यापारियों और उद्योगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जीएसटी लागू होने से उनकी कठिनाईयां बढ़ रही हैं और धंधा भी चौपट हो रहा है। निर्यातकों की भी जीएसटी से कई प्रकार की शिकायतें रही हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें बिना टैक्स के माल निर्यात करने की इजाजद थी, लेकिन अब उन्हें पिछले करों का क्रेडिट मिलने में कठिनाई हो रही है। इसके कारण चिंतित सरकार ने जीएसटी से संबंधी कठिनाईयों से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। 7 अक्टूबर 2017 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और निर्यातकों को राहत देने के लिए सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि 75 लाख के बजाय 1 करोड़ की टर्नओवर वाले उद्यमों पर कम्पोजिट स्कीम लागू हो गई और व्यापारियों के लिए 1 प्रतिशत, उत्पादकों के लिए 2 प्रतिशत और रेस्टोरेंट के लिए 5 प्रतिशत की दर से कम्पोजिट टैक्स भरने का प्रावधान रख गया। जिसे अब सभी के श्रेणियों के लिए 1 प्रतिशत कर दिया गया है। अनुपालन के दर्द को कम करने के लिए यह प्रावधान रखा गया है कि अब उन्हें मासिक रिटर्न के बजाय तीन महीने में एक रिटर्न भरनी होगी। इससे पहले अपंजीकृत विक्रेता से माल खरीदने पर रिवर्स चार्ज देना पड़ता था यानि उसका भी टैक्स खरीदने वाले को भरना पड़ता था, इस प्रावधान को 31 मार्च 2018 तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा कई उत्पादों पर टैक्स को कम कर दिया गया है। जिन ठेको में श्रम का हिस्सा ज्यादा है, उनपर मात्र 5 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा। सरकार ने यह भी वायदा किया है कि एक बार राजस्व ठीक–ठाक मिलना शुरू हो जाए तो करों को और भी कम किया जा सकेगा।

यही नहीं, लघु उद्यमियों की हमेशा यह शिकायत रही है कि छोटे–बड़ों को एक ही जैसा व्यवहार दिए जाने के कारण उनकी प्रतिस्पर्द्धा शक्ति क्षीण हो रही है, इससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि लघु उद्यमियों द्वारा दिए गए करों का कुछ हिस्सा उन्हें वापिस किया जाए। ऐसा लगता है कि इन फैसलों से लघु उद्यमियों का जीएसटी दर्द पहले से काफी कम हो जाएगा। ❑❑

विश्व भूख सूचकांक, भारत व स्वदेशी की रीति-नीति

विश्व में भुखमरी की 119 देशों की 2017 की सूची में भारत का 100वें स्थान पर आना गंभीर रूप से चिंताकारक व देश में कल्पनातीत कुपोषण, आर्थिक विषमता व अभावों का सूचक है। विगत 26 वर्षों से चल रहे आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किये आयात उदारीकरण, विदेशी निवेश प्रोत्साहन एवं श्रम आकस्मिकीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों व रोजगार की गुणवता में आयी गिरावट का यह परिणाम है। वर्ष 2014 में भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक (वर्ल्ड हंगर इण्डेक्स) में 55वें स्थान पर था। लेकिन, तब यह गणना कुल 76 देशों के आधार पर की थी। इसलिए तीन वर्ष में ही भारत के 45 स्थान नीचे फिसलने की बात सही नहीं है। वैसे वर्ष 2011 से ही कुपोषण से उबरते हुये भारत 2011 के 67वें स्थान से 2012 व 2013 में क्रमशः 66वें व 63वें स्थान पर आकर 2014 में 55वें स्थान पर पहुंचकर एक अत्यंत ही हर्षकारक अनुभूति का कारक रहा है। गणना की पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण भारत 2015 में 80वें, 2016 में 97वें स्थान पर फिसलने के बाद सौवें स्थान पर फिसलकर नेपाल, म्यामार, बांग्लादेश व श्रीलंका से भी नीचे पहुंच गया है। अन्यथा भारत के भुख के सूचकांक में इन वर्षों में कमी आई है। तथापि गरीबीवश देश में आज भी 19.4 करोड़ लोग भूखे सोते बताये जाते हैं। पोषण की कमी, बढ़ते बाल कुपोषण आदि से हमारी आगामी पीढ़ी की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित होगी। कुपोषण से हमारे 5 वर्ष तक की आयु के 21 प्रतिशत बच्चे नष्ट बालपन से त्रस्त है, जिनका अपनी ऊँचाई की तुलना में भार गंभीर रूप से न्यून है। दूसरी ओर लगभग 40 प्रतिशत बच्चों की ऊँचाई ही उनकी आयु से अति न्यून है, जिन्हें स्टण्टेड कहा जाता है। पाँच वर्ष से अल्प आयु तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर भी देश में 4.8 प्रतिशत है जो विश्व में अत्यंत उच्च है। वस्तुतः इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण रोजगाररहित आर्थिक वृद्धि है। इसलिए देश में रोजगार

वैश्विक भुखमरी सूचकांक गणना की पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण भारत 2015 में 80वें, 2016 में 97वें स्थान पर फिसलने के बाद सौवें स्थान पर फिसलकर नेपाल, म्यामार, बांग्लादेश व श्रीलंका से भी नीचे पहुंच गया है।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

वैश्विक भुखमरी सूचकांक

देश	*भूख सूचकांक में स्थान*
चीन	29
नेपाल	72
म्यांमार	77
श्रीलंका	84
बांग्लादेश	58
भारत	100
पाकिस्तान	106

2010 के दशक में भारत का भूख सूचकांक

देश	*भूख सूचकांक में स्थान*
चीन	29
नेपाल	72
म्यांमार	77
श्रीलंका	84
बांग्लादेश	58
भारत	100
पाकिस्तान	106

1992–2017 में भूखमरी पर नियंत्रण में सफलता

देश	*भूखमरी पर नियंत्रण*
चीन	71 प्रतिशत
म्यांमार	59 प्रतिशत
बांग्लादेश	51 प्रतिशत
नेपाल	48 प्रतिशत
भारत	32 प्रतिशत
पाकिस्तान	24 प्रतिशत
श्रीलंका	19 प्रतिशत

कुछ एशियाई देशों में भुखमरी स्कोर की तुलना

देश	*भुखमरी स्कोर**	
	1992	2017
चीन	25.9	7.5
नेपाल	42.5	22
म्यांमार	55.6	22.6
श्रीलंका	31.6	25.5
बांग्लादेश	53.6	26.5
भारत	46.2	31.4
पाकिस्तान	42.7	32.6

* जिस देश का स्कोर जितना कम होता है, वहाँ भुखमरी उतनी ही कम होती है। भारत की तुलना में अधिकांश देश इस स्कोर में भारी कमी करने में सफल हुए हैं।

पाँच वर्ष से अल्प आयु के नष्ट–शैशव युक्त बच्चे का प्रतिशत

देश	*नष्ट शैशव ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत*
चीन	1.8
म्यांमार	7
पाकिस्तान	10.5
नेपाल	11.3
बांग्लादेश	14.3
भारत	21
श्रीलंका	21.4

सृजन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गुणवता वाले रोजगार के अभाव में ही भुखमरी के अधिकांश मानकों में हम अपने अधिकांश एशियाई पड़ौसियों से बहुत पीछे है। इसे निम्न तालिकाओं से देखा जा सकता है।

वस्तुतः 26 वर्षों में लागू आर्थिक सुधारों के दौर में जहाँ देश से उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कियाओं के देश से बाहर जाने और विदेशों में उत्पादित मूल उपकरणों व हिस्से पुर्जों को देश के बाहर से लाकर भारत में उत्पादों को मात्र एसेंबल किये जाने से देश मात्र एसेंबली लाइनों वाले देश में बदल गया है। इससे देश केवल रोजगारविहीन आर्थिक वृद्धि का शिकार ही नहीं हुआ वरन, इससे रोजगार सृजन में भारी गतिह्रास हुआ है, रोजगार का आकस्मिकीकरण हुआ है, सामाजिक सुरक्षा में ह्रास हुआ और रोजगार की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है। इससे कुपोषण, मानसिक अवसाद, परिवार विच्छेद और पारिवारिक व वैयक्तिक तनावों में भारी वृद्धि हुयी है।

आर्थिक सुधारों के बाद रोजगार सृजन व रोजगार की गुणवत्ता (क्वालिटी ऑफ एम्पलायमेंट) में आयी भारी गिरावट, रोजगार की असुरक्षा नियमित व सामाजिक सुरक्षा युक्त रोजगार में भी भारी गिरावट और अनियमित व आकस्मिक रोजगारों में अति न्यून पारिश्रमिक के कारण 12 से 16 घंटे काम करने की विवशताओं के चलते ही भारत भुखमरी के सूचनांक में फिसल कर 100वें स्थान पर पहुंच चुका है। महानगरों में बड़े भवनों में सुरक्षा के काम में लगे कई सुरक्षा गार्ड 4 से 7 हजार रूपये मासिक में दो–दो नौकरियाँ या दो–दो शिफ्ट में काम कर अपना परिवार पालते मिल जाएंगे, जबकि विहित न्यूनतम मजदूरी 9000 रुपये हैं कस्बों में 3500 से 5000 रुपये में काम करते लोग मिल जाते हैं। गांवों व कस्बों में निजी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक–शिक्षिकायें 3–6 हजार रूपये मासिक में और महाविद्यालयों में 7–8 हजार रूपये मासिक में सेवारत प्राध्यापक मिल जायेंगे, जो यूजीसी द्वारा विहित वेतन के एक चौथाई से कम है। शासकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पीएचडी युक्त, युवक–युवतियां 500 रूपये प्रति कालांश लेकर 10–10 वर्षों से जीवन ढो रहे हैं। वहां भी उन्हें अतिथि संकाय में बने रहने के लिये जिस प्रकार के समझौते करने होते है और जिस तनाव का शिकार होते हैं, वह अलग है।

इसी वर्ष फरवरी 6, 2017 को संसद में दिये एक उत्तर में श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि 2013–14 से 2015–16 के बीच वर्ष में 30 दिन भी काम नहीं करने वाले श्रमिकों का अनुपात भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 हुआ है। इस प्रकार के रोजगार को श्रम मंत्रालय यूपीएसएस (Usual Principal & Subsidiary Status) कहता है। आर्थिक

प्रमुख देशों में 15–29 वर्षीय युवा जो न रोजगार में है और न ही अध्ययनरत या प्रशिक्षणरत

देश	चीन	रूस	ब्राजील	अर्जेण्टाइना	कोलम्बिया	इंडोनेशिया	**भारत**	द.अफ्रीका	ओईसीडी समूह के औद्योगिक देश–यूरोप व अमेरिका सहित
बेरोजगारी अनुपात प्रतिशत	11.32	14.04	19.96	20.3	20.62	23.24	**30.83**	36.65	14.56

सहयोग व विकास संगठन (आई.सी.डी.) के अनुसार तो देश के 30.8 प्रतिशत युवा आज रोजगाररहित है। देश में 15–29 वर्ष के युवा जो आज न तो किसी काम या रोजगार में संलग्न है और न ही वे कहीं पढ़ाई कर रहे है या कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश भारत है। इन्हें No Employment, Education and Training (NEET) Youth कहते हैं।

वस्तुतः, भुखमरी की इन उपरोक्त परिस्थितियों के पीछे बहुत बड़ा कारण नियमित व गुणवत्ता युक्त रोजगार का अभाव है। देश के 77 प्रतिशत परिवारों का कोई एक सदस्य तक भी किसी प्रकार के नियमित रोजगार में अर्थात नियमित मजदूरी अर्जनकर्त्ता नहीं है और कुल श्रमिकों में से भी केवल 60.6 प्रतिशत श्रमिक ही ऐसे हैं, जिन्हें वर्ष भर ऐसा आकस्मिक काम भी मिल पाता हैं। नगरीय क्षेत्र में महिला बेरोजगारों का प्रतिशत तो आज 12 प्रतिशत के अति उच्च स्तर पर है। नियमित मजदूरी या वेतन पर नियुक्त कार्मिकों की संख्या तो देश में आज मात्र 17 प्रतिशत ही रह गयी है और 71.2 प्रतिशत कार्मिकों को उनके रोजगार के संबंध में आज कोई सामाजिक सुरक्षा सुलभ नहीं है।

यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि नोटबंदी व रेरा में आरोपित नियंत्रणों के फलस्वरूप निर्माण के क्षेत्र में आने वाली नयी परियोजनाओं में भारी कमी आयी हैं व पूर्व अनुमोदित परियोजनाएं में भी बड़ी संख्या में स्थगित हुयी है। इससे सामान्य रेत व गिट्टी ट्रकों में भरने वाले श्रमिकों से लेकर कारीगर, प्लम्बर, छत डालने वाले, वायरमेन आदि के रोजगार व भवन निर्माण से लेकर सेनीटरी व विद्युत उपकरणों तक सभी प्रकार के व्यवसायों में कारोबार का ह्रास हुआ ही है। एक बार आये भारी गतिरोध के बाद आज भी जुलाई से सितंबर के बीच वार्षिक आधार पर देश के सभी प्रमुख केंद्रों पर गृह बिक्री की मात्रा में 32 प्रतिशत की गिरावट आयी है। वस्तु सेवा कर की नयी व्यवस्था में अनेक छोटे उद्यम भी प्रभावित हुये हैं। आर्थिक दृष्टि से अनेक क्षेत्र मंदी का अनुभव करने लगे हैं। वस्तु व सेवा कर से देश में जहाँ कर चोरी लगभग बीते युग की बात हो जायेगी। लेकिन छोटे व्यवसाय भी इससे प्रभावित होंगे। साधारण दैनिक मजदूरी अनेक व्यक्ति को इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। उसे तो जो रोजगार मिलता रहा है वह मिलता रहे। इसके अतिरिक्त देश में 10–12 लाख नये युवा प्रतिमाह व 1.2 से 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की आयु प्राप्त कर रहे हैं। इसलिये प्रतिवर्ष न्यूनतम 1.2 करोड़ नवीन रोजगार सृजन हेतु, विशेषकर विनिर्माणी उत्पादन अर्थात मेन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश आवश्यक है।

रोजगार में संख्यात्मक व गुणात्मक सुधार के लिये आज देश में विनिर्माणी–उत्पादन अर्थात मेन्यूफेक्चरिंग में द्रुतवृद्धि व रोजगार सृजनकारी निवेश पहली आवश्यकता है। चीन का वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन अर्थात ग्लोबल मेन्यूफेक्चरिंग में आज भारत के 2.1 प्रतिशत की तुलना में 22 प्रतिशत अंश होने से, चीन की जनसंख्या में मध्यम आय वर्ग का अनुपात विश्व में सर्वोच्च हो गया है। जबकि हमारे यहाँ मेन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र में, घरेलू निवेश में पिछड़ते चले जाने से आज विश्व के सर्वोच्च, 31 प्रतिशत निर्धन बच्चे भारत में हैं। विगत कुछ (10–12) वर्षों से भारत में उत्पादन के क्षेत्र में घरेलू निवेश के प्रस्तावों में आयी द्रुत गिरावट, आयातों की अधिकता एवं आय व मांग में वृद्धि के अभाव में ही नवीन घरेलू निवेश की स्थिति इस चिंताजनक स्थिति में पहुंची है। दूसरी ओर निवेश व घरेलू विनिर्माणी उत्पादन (डोमेस्टिक मैन्युफेक्चरिंग) के

पक्ष में वांछित वातावरण के अभाव में, फैलती औद्योगिक रूग्णता के कारण अनेक बड़े उद्यम या तो विदेशी निवेशकों द्वारा अधिग्रहीत कर लिये गये हैं या वे दिवालियापन की कार्यवाही में फँस गये हैं। एस्सार आइल बिकी, उसे रोजनिफ्ट नामक रूसी कंपनी ने खरीदा, ग्लेण्ड फार्मा को चीनी कंपनी फोसन ने खरीदा। विगत 2 वर्षों में 2 लाख करोड़ रूपयों से अधिक मूल्य के घरेलू स्वामित्व वाले उत्पादन संसाधन विदेशी नियंत्रण में गये हैं। व्यवसाय के लिये अनेक असहजताओं के चलते एस्सार स्टील, भूषण स्टील, मोन्नेट इस्पात, जेपी इन्फ्राटेक, भूषण पॉवर ए.बी.जी. शिपयार्ड जैसी बड़ी और एक दर्जन से अधिक कंपनियों को दिवालिया घोषित कराने की पहल भी रिजर्व बैंक ने की है।

आज देश में घरेलू विनिर्माणी उत्पादन (डोमेस्टिक मैन्यूफेक्चरिंग) के लिये आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) नहीं रह जाने के कारण स्टेशनरी, फर्नीचर व अस्तर के कपड़ों से लेकर टायर, सोलर पेनल, मोबाइल फोन, विद्युत उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक साज–सामान तक अधिकांश उत्पाद चीन, यूरो–अमेरिकी देशों व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आता चले जा रहे हैं। वहाँ पर उन देशों की सरकारों द्वारा प्रभावी उद्योग सहायता संघों अर्थात इंडस्ट्री कॉन्सोर्टियमों और सस्ती बिजली व अल्प ब्याज दरों आदि से प्रदत्त बेहतर, अधिक अनुकूल व उनके घरेलू विनिर्माणी उत्पादन के लिये अत्यंत मैत्रीपूर्ण पारिस्थितिकी–तंत्र (मेन्यूफेक्चरिंग फ्रेण्डली इको–सिस्टम) होने से देश के अनगिनत उद्योग व सौ से अधिक उद्योग संकुल (इण्डस्ट्री क्लस्टर्स) रूग्णता की ओर बढ़ रहे हैं।

देश की रोजगार क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं का कारण विगत 26 वर्षों के तथाकथित सुधारों के दौर में हमारी विदेश निवेश की मृग–मरीचिका में फंसते

हमें केवल ''मेड इन इंडिया'' देखकर ही नहीं, वस्तुतः वे 'मेड बाई भारत' अर्थात 'मेड बाई इंडिया' उत्पाद व सेवा के ब्राण्ड की श्रेणी में आते हैं या नहीं, इसे भी देखना होगा।

चले जाना है। विदेशी निवेशक उनके उत्पादों के अधिकांश हिस्से पुर्जे देश के बाहर से लाकर हमारे देश में उनके उत्पादों को केवल जोड़ने का काम करते हैं। उसमें हमारा मूल्य योगदान (वेल्यू एडिशन) अत्यंत स्वल्प होता है। उदाहरण के लिये स्मार्ट फोन के उत्पादन में कंपनियों का भारत में मूल्य योगदान 6 प्रतिशत से कम है और 94 प्रतिशत से अधिक मूल्य संवर्द्धन विदेशों में होता है। विदेशी उत्पाद व ब्राण्ड जो मेड इन इंडिया तो है पर उनमें अधिकांश में नाममात्र का मूल्य संवर्द्धन भारत में हो रहा है।

विदेशी कंपनियां तो अपना आइसक्रीम मिक्स तक विदेश से ही ला रही हैं। इसलिये देश में रोजगार सृजन रोजगार की गुणवत्ता का विस्तार, घरेलू प्रौद्योगिकी विकास, रोजगार–सृजक घरेलू निवेश प्रोत्साहन के लिये 'मेड बाई इंडिया' उत्पाद ब्राण्डों व सेवाओं को प्रोत्साहन व समर्थन देना है। उदाहरणार्थ जूते के पॉलिश में रॉबिन व गेही पॉलिश, बल्बों व ट्यूब लाइटों में सूर्या, बजाज आदि दूध आइसक्रीम व चॉकलेट में अमूल, वाडीलाल, सरस, सांची आदि तो 'मेड बाई भारत' है। लेकिन इन्हीं उत्पादों में क्रमशः चेरी पॉलिश, फिलिप्स या हुवाई या नेस्ले आदि विदेशी ब्राण्ड हैं।

आज चीन उसके एम.आई. 4, स्मार्ट फोन को मेड इन इंडिया लिखकर नाममात्र के लिये देश में एसेम्बल कर रहा है। इसलिये हमें केवल ''मेड इन इंडिया'' देखकर ही नहीं, वस्तुतः वे 'मेड बाई भारत' अर्थात 'मेड बाई इंडिया' उत्पाद व सेवा के ब्राण्ड की श्रेणी में आते हैं या नहीं, इसे भी देखना होगा। यदा–कदा यह भ्रम भी खड़ा कर दिया जाता है कि अवसंरचना क्षेत्र में यथा सड़क निर्माण, रेल विस्तार, मेट्रो या बुलेट ट्रेन, पॉवर प्लांट, टेलिफोन एक्सचेंज, सोलर पार्क आदि का काम विदेशी निवेशकों को सौंप देने चाहिये। यह और भी खतरनाक हैं।

देश में उत्पादन व रोजगार क्षति का एक बड़ा कारण अवसरंचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र अर्थात रेलवे उपकरण (मेट्रो ट्रेन से बुलट ट्रेन, ट्रेन के इंजिन व अनेकों उपकरण व पार्ट्स) पॉवर प्लाण्ट व उनके साज–सामान, सोलर पेनल, प्रिण्टिंग मशीनरी, टेक्सटाईल मशीनरी आदि के आयातों को प्राथमिकता की नीतियों के कारण देश में औद्योगिक साज–सामान (आरिजिनल इक्विपमेण्ट मेन्युफेक्चरिंग) व मशीन टूल सेक्टर विलोपित ही होते जा रहे हैं। यदि, जैसी भी सम्भव हो 1 लाख करोड़ रूपये की लागत वाली बुलेट ट्रेन हम देश में बनायें तो उसकी निम्नवर्ती मूल्य श्रृंखला (डाउनस्ट्रीम वेल्यू चैन) व क्षैतिजिक मांग व प्रतयावर्तन पर गुणकीय प्रभाव (हॉरिजोण्टल डिमाण्ड एण्ड टर्नऑवर मल्टीप्लायर इम्पेक्ट) से 10 लाख करोड़ रूपये से अधिक के उत्पादन, रोजगार व कारोबार का सृजन होता है। इसलिये आज यदि अर्थव्यवस्था को उत्पादन व रोजगार सृजन में आये

गतिरोध से उबारना है एवं विनिर्माणी उत्पादन (मेन्युफेक्चरिंग) के क्षेत्र में देश को 2.1 प्रतिशत के स्तर से एक सम्मानजनक स्थिति में लाना है तो हमें उद्योग सहायता संघों (इण्डस्ट्री कन्सोर्टियम) विकास, घरेलू पूंजी निवेश व देश में मूल–उपकरणों के उत्पादन व अवसरंचना संबंधी उत्पादक उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। विदेशी निवेश आश्रित अर्थव्यवस्थाओं के विकास की विश्व में कहीं कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया से चीन पर्यन्त व उससे पूर्व के दौर में यूरोप से अमेरिका पर्यन्त सभी देश अपने घरेलू संसाधनों से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के साथ आर्थिक व तकनीकी राष्ट्रवाद के मार्ग पर आगे बढ़कर ही उत्पादन के क्षेत्र में आज की उन्नत अवस्था में पहुँचे हैं। हम विश्व की 17. 8 प्रतिशत जनसंख्या है। लेकिन, वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन (वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग) में हमारा अंश मात्र 2.1 प्रतिशत है, चीन का 22 प्रतिशत अमेरिका का 17.6 प्रतिशत व जापान का 7 प्रतिशत है।

जापान का विश्व जनसंख्या में अनुपात मात्र 1.6 प्रतिशत ही है, पर वर्ल्ड मैन्युफेक्चरिंग में उनका अंश 7 प्रतिशत है। विश्व के लिये सर्वाधिक उन्नत बसें व ट्रकें (ए.बी.एस. वॉल्वो व स्केन्या आदि) यदि, मात्र 80 लाख जनसंख्या वाला देश स्वीडन बनाता है। विश्व में जहाज निर्माण के क्षेत्र में हमारी जनसंख्या व क्षेत्रफल की तुलना में 5 प्रतिशत जनसंख्या व 5 प्रतिशत क्षेत्रफल वाला दक्षिण कोरिया, 25 प्रतिशत अंश के साथ प्रथम स्थान रखता है। हमारा तो वर्ल्ड शिप–बिल्डिंग में मात्र 1.0 प्रतिशत अंश है, जबकि हम विश्व के चौथे सबसे बड़े स्पात उत्पादक देश हैं। स्पात उत्पादन में तो प्रकृति ने साथ देकर हमें प्रचुर खनिज लोह अयस्क प्रदान किया है। लेकिन जहाज निर्माण हेतु तो घरेलू सामुद्रिक अभियांत्रिकी (मेरिटाइम इजिनीयरिंग) को अपने साधनों से विकसित करना होगा। जब तक हम भी औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में उन्नत देशों की तरह, स्वदेशी, स्वावलम्बी आर्थिक विकास, आन्तरिक पूंजी निवेश, आर्थिक राष्ट्रवाद और तकनीकी राष्ट्रवाद अर्थात टेक्नो नेशनलिज्म का अनुसरण नहीं करेंगे। तब तक हम आर्थिक, तकनीकी, अवसंरचना विकास और गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पायेंगे। अस्तु–ऐसा ही हो। इस हेतु इस लेख की आगामी क्रमिक अंशिकाओं में इन्हीं विषयों का यथोचित विवेचन किया जायेगा।

इन आगामी अंशिकाओं में प्रौद्योगिकी विकास, घरेलू पूंजी का निर्माण, घरेलू निवेश के सुगमीकरण आदि पर चर्चा केंद्रित करते हुये 'मेड बाई भारत' की रीति नीति को विवेचित किया जायेगा। ...

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

चौराहे पर विश्व–व्यवस्था

वर्तमान विश्व–व्यवस्था दोराहे से चौराहे पर आ खड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट रूप से दो ही रास्ते थे। सोवियत संघ के नेतृत्व में लामबंद साम्यवादी और अमेरिका के पूंजीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित उसके साथी। साम्यवाद अपने ही खोदे गड्डे में दफन हो गया। पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व व्यापार संगठन का मुखौटा लगाकर दुनिया भर में छा गया। मगर इसकी नकेल पश्चिम के ही हाथों से चीन छिनने को बेकरार है। जहां पर पूंजीवाद और मार्क्सवाद का घालमेल है।

नई विश्व–व्यवस्था चौराहे पर खड़ी होकर ग्रीन–सिग्नल का इंतजार कर रही है। इसके एक तरफ अमेरिका और उसका अविश्वसनीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग। इसी चौराहे पर विश्व में महाशक्ति घोषित होने की हसरत पाले चीन भी है तथा एक ओर इस्लामी आतंकवाद। विश्व व्यवस्था के इस चौराहे पर एक प्रकार से शंतरज की बिसात बिछा दी गई हैं, शह और मात के खेल में इतना घालमेल है कि सामने वाला खिलाड़ी अपने सफेद मोहरों को छोड़कर दुश्मन के काले मोहरों से खेलने लग जाता है।

भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश जहाँ विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसता है, उनको विश्व व्यवस्था में सही सहभागिता देनी होगी। सामूहिक नेतृत्व की भावना से प्रेरित नई विश्व–व्यवस्था के माध्यम से विश्व को उन्नति और शांति के पथ पर चलने की जरूरत है।
– दुलीचन्द रमन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने चुनाव के दौरान चीन को पानी पी–पीकर कोसता था आज वही अमेरिका उत्तर कोरिया को साधने के लिए चीन के साथ गलबहियाँ कर रहा है। चीन के भी अपने स्वार्थ है। वह कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका कभी चैन से बैठे। चीन का मानना है कि अगर उत्तर–कोरिया का संकट खत्म हो गया तो किम जोंग की सत्ता चली जायेगी। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के एकीकरण की मांग उठेगी। जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में चीनी हस्तक्षेप और व्यापार खत्म हो जायेगा। चीन को लगता है कि उत्तर कोरिया बुरा सही, पर दुश्मन का दुश्मन तो है। इस लिहाज से उसे अपना माना जा सकता है।

अमेरिका को लगता है कि चीन से बाद में निपटा जा सकता है। पहले किम जोंग की मिसाईलों का मुँह तो मोड़ लिया जाये, चाहे इसके लिए दो–चार दिन एक दुश्मन को गले लगाना पड़े। उत्तर कोरिया का तानाशाह हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैंस होने के कारण अमेरिका उस पर सीधी सैन्य कार्यवाही करने से बचेगा। केवल आर्थिक प्रतिबंधों से काम चलाना पड़ेगा। उत्तर कोरिया हर दिन अमेरिका के मित्र देशों जापान और दक्षिण कोरिया को डराता रहता है। दक्षिण कोरिया ने अपनी सुरक्षा हेतु मिसाईल रोधी सिस्टम "थाड" अपने यहाँ स्थापित कर लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ की एक कंपनी 'लोटो' ने भी कुछ जमीन मुहैया करवा दी। इस ब्रांड के कुछ स्टोर चीन में भी खुले थे। चीन ने 'लोटो' कंपनी पर हास्यास्पद आरोप लगाकर उसके स्टोरों को बंद करवा दिया। लोटो कंपनी अब चीन से अपना व्यापार समेट रही है। चीन की यह कार्यवाही कुछ–कुछ उत्तर–कोरिया की पीठ पर हाथ रखने जैसी है।

जापान के द्वीपों के आसमान से हर दिन कोई न कोई किम जोंग की मिसाईल गुजरती है। जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता है। लेकिन अमेरिका 'ट्रंप काल' में खुद

को वैश्विक मामलों से समेट रहा है। डोकलाम विवाद के दौरान जापान द्वारा भारत के पक्ष में वक्तव्य देने से भी चीन नाराज है। इस क्षेत्र में चीन और उत्तर कोरिया की जुगलबंदी तथा अमेरिका का अविश्वश्नीय रवैया जापान को एक अलग रणनीति बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है। जापान ने बहुत सोच–समझकर ही एशिया की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मोदी के बीच इस दौरान कई वार्ताओं के साथ–साथ व्यक्तिगत समझ भी विकसित हो चुकी है। चीन की 'वन बेल्ट–वन रोड (ओबोर)' की महत्त्वाकाक्षी परियोजना के समानांतर "एशिया अफ्रीका विकास गलियारे" के निर्माण के लिए भारत और जापान ने हाथ मिला लिया है। जिसमें दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने "चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे" के विरोध स्वरूप ओबोर परियोजना का बहिष्कार किया था। चीन की हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ रही नौसैनिक गतिविधियों के मद्देनजर भारत–जापान– अमेरिका ने मिलकर इस समुद्री क्षेत्र में मालाबार–2017 नाम से नौसैनिक अभ्यास किया है। अब सिंगापुर और आस्ट्रेलिया भी इस नौसैन्य अभ्यास में संयुक्त अभ्यास के लिए उत्सुक है। चीन जिस प्रकार से दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में मनमानी चला रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। उसे देखते हुए यह गठजोड़ भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

मध्य पूर्व में भी अमेरिका उहापोह की स्थिति में है। ट्रंप मध्य पूर्व की यात्रा पर सबसे पहले सउदी अरब पहुँचे। यह सिया बहुल देश ईरान को साधने के लिए सुन्नी अरब जगत के साथ खड़ा होने की कोशिश थी। सउदी अरब और पाकिस्तान में नजदीकियाँ हैं। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से लताड़ चुका है। पाकिस्तान अभी तक अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों के खिलाफ कार्य कर रहा है। पाकिस्तान वहां की अफगान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में वहां के तालीबानों की मदद कर रहा हैं।

बदलते परिवेश में अमेरिका अब अफगानिस्तान में भारत के लिए 'नई अफगान नीति' में महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहता है। भारत पिछले कई वर्षों में आतंकवाद से ग्रस्त अफगानिस्तान में लोकतंत्र व शांति बहाली के लिए कार्य करता आ रहा है। लेकिन भारत को अब अफगानिस्तान संबंधी अमेरिका की नई नीति के अतंर्गत फूक–फूककर कदम रखने की जरूरत है। इसमें दूसरों की आग में अपने हाथ जल जाने का खतरा भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने सैनिक अफगानिस्तान में भेजें, ताकि अमेरिका वहां से अपने सैनिक निकाल सके। भारत अभी तक वहां चिकित्सा सड़क परिवहन, विद्युत व सिंचाई के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है, आगे भी असैनिक क्षेत्र में ही अपनी भूमिका जारी रखे। यहीं भारत के हित में होगा। क्योंकि वहां पर गृह युद्ध का लंबा इतिहास है।

बदलते परिवेश में अमेरिका अब अफगानिस्तान में भारत के लिए 'नई अफगान नीति' में महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहता है।

मध्यपूर्व में इस्लामिक आतंकवाद अपनी जड़े गहरी जमा चुका है। धार्मिक कट्टरता, कबीलाई संस्कृति, घरेलू परिस्थितियाँ तथा अतंर्राष्ट्रीय राजनीति ने इस क्षेत्र को आतंकी गतिविधियों का अखाड़ा बना दिया है। शीत युद्ध के दौरान सोवियंत संघ और अमेरिका ने इस क्षेत्र की धार्मिक कट्टरता का प्रयोग एक–दूसरे को शह–मात देने के लिए किया। वर्तमान में आई.एस.आई., इराक और सिरिया में अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इस विचारधारा का इतनी आसानी से खात्मा नहीं किया जा सकता। खाड़ी युद्ध की यादे अब धुंधली पड़ने लगी है सद्दाम हुसैन को नई पीढ़ी नहीं जानती, पर इराक अभी तक सुलग रहा है।

अमेरिका व दूसरी शक्तियों को इस क्षेत्र में फूक–फूककर कदम रखने चाहिए, अन्यथा जब आग लगती है तो वह अपना–पराया नहीं देखती। अतंर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसलों और आतंकवाद को अलग–अलग किया जाना बहुत जरूरी है, इस बारे में दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उन देशों और संस्थाओं को भी सीमित बयानबाजी से आगे जाकर कड़े संदेश देने होगें जो विभिन्न मसलों का बहाना बनाकर आतंकवाद के पैरोकार बन जाते है।

संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व व्यवस्था की नियामक इकाई है, वह दिन–प्रतिदिन अप्रासंगिक होती जा रही है। वीटो के अधिकार प्राप्त कुछ देश निजी स्वार्थों हेतु इसका उपयोग करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था से हम काफी आगे निकल आये है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश जहाँ विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसता है, उनको इस व्यवस्था में सही सहभागिता देनी होगी। सामूहिक नेतृत्व की भावना से प्रेरित नई विश्व–व्यवस्था के माध्यम से विश्व को उन्नति और शांति के पथ पर चलने की जरूरत है। ❑❑

एच1बी वीजा पर साहस दिखाइए!

भारतीय इंजीनियरों द्वारा अमेरिका को पलायन करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एच1बी वीजा का उपयोग किया जाता है। इस वीजा के अंतर्गत विदेशी इंजीनियरों को 6 वर्षों तक अमेरिका में काम करने की छूट होती है। इस वीजा को जारी करवाने के लिए अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी सरकार को अर्जी देनी होती है। इन्हें प्रमाणित करना होता है कि वांछित क्षमता के इंजीनियर अमेरिका में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें विदेशी इंजीनियरों को रखने की अनुमति दी जाए। इस वीजा का उपयोग करके हर वर्ष एक लाख से अधिक भारतीय इंजीनियर अमेरिका को पलायन करते है। इस पलायन के अमेरिका पर दो प्रभाव पड़ते है। सुप्रभाव यह पड़ता है कि अमेरिकी कंपनियों को श्रेष्ठ क्वालिटी के इंजीनियर उपलब्ध हो जाते हैं। ये इंजीनियर अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बनाते है जैसे नई दवाओं का आविष्कार करते हैं अथवा अच्छे साफ्टवेयर बनाते हैं। इनके इस योगदान से अमेरिकी कंपनियां विश्व में आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकी इंजीनियरों पर इस पलायन का दुष्प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी कंपनियों की लगातार आलोचना होती रही है कि ये एच1बी वीजा का दुरूपयोग करके सस्ते भारतीय इंजीनियरों को नौकरी देते है और तुलना में मंहगे अमेरिकी इंजीनियर बेरोजगार रह जाते हैं। तर्क है कि अमेरिका में उच्च कोटि के इंजीनियर उपलब्ध है। केवल सस्तेपन के चलते एच1बी के अंतर्गत भारतीय इंजीनियरों का आयात किया जाता है।

अमेरिकी कंपनियों की लगातार आलोचना होती रही है कि ये एच१बी वीजा का दुरूपयोग करके सस्ते भारतीय इंजीनियरों को नौकरी देते है और तुलना में मंहगे अमेरिकी इंजीनियर बेरोजगार रह जाते हैं। तर्क है कि अमेरिका में उच्च कोटि के इंजीनियर उपलब्ध है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताए गए दुष्प्रभाव को ज्यादा महत्व दिया है। एच1बी वीजा जारी करने के नियमों को सख्त बनाना चालू कर दिया है। इस दिशा में तीन परिवर्तन किए हैं। पहला यह कि वीजा धारक को उसी कंपनी के लिए कार्य करना होगा जिसके द्वारा एच1बी वीजा की अर्जी पर वीजा जारी हुआ है। अक्सर अमेरिकी कंपनियाँ बड़ी संख्या में एच1बी वीजा जारी करा लेती है। उसके बाद भारत से आए इंजीनियरों को मनचाही अमेरिकी कंपनी को स्थानांतरित कर देती है। दूसरे, पूर्व में एच1बी वीजा धारक के पति

अथवा पत्नि को आसानी से अमेरिका में कार्य करने की इजाजद मिल जाती थी। तीसरा, अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के परिजनों को अमेरिका में प्रवेश देने पर ट्रंप प्रतिबंध लगा रहे है। ट्रंप द्वारा लिए गए इन कदमों से भारतीय इंजीनियरों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा।

ट्रम्प द्वारा उठाया गया यह कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए हानिप्रद होगा। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठतम इंजीनियरों की मांग है। जैसे किसी कंपनी द्वारा साफ्टवेयर बनाने की टीम में तीन भारतीय, दो अमेरिकी, एक मेक्सिकन, दो इजराइयली एवं एक पाकिस्तानी नागरिक है। कंपनी वैश्विक स्तर पर टैलेंट खोजती है। अब यदि केवल अमेरिकी इंजीनियरों से काम लेना हो तो भारतीय आदि विदेशियों की उत्कृष्ठ क्षमता से कंपनी वंचित हो जाएगी और कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने की ताकत का ह्रास होगा। तत्काल अमेरिकी इंजीनियरों को मिलने वाले रोजगार अवश्य बढ़ेगें, परंतु 2–4 वर्षों में ही अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक ताकत कम हो जाएगी और वे विश्व बाजार में पिछड़ेगी। बहरहाल यह अमेरिका की बात है। हमें देखना है कि हम ट्रंप की नई नीति का सामना किस प्रकार करें।

एच1बी पर प्रतिबंध लगाने से भारतीय इंजीनियरों का अमरीका को पलायन कम होगा। इसका भारत पर सीधे दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे गांव का युवा शहर को पलायन न कर पाए तो शहर से भेजी जाने वाली रकम से गांव वंचित हो जाएगा। लेकिन वहीं युवा यदि गांव में रहकर दुकान अथवा कुटीर उद्योग लगाए तो गांव पर तमाम सुप्रभाव पड़ेंगे। गांव की आय बढ़ेगी। दुकान में 2–3 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी गांव पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि गांव की सुविधाएं कैसी है। मेरे पास हाल में एक 30 वर्षीय व्यक्ति रोजगार मांगने आया। वह 10,000 रुपए प्रतिमाह पर किसी कंपनी में कार्यरत है। उन्होंने गांव से पलायन किया और रोजगार पाया। लेकिन उनके छोटे भाई ने गांव में ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की दुकान लगा ली। उसने पलायन नहीं किया। आज उसने अपनी कमाई से निजी मकान बना लिया है जबकि पलायनकर्ता किराए के मकान में रह रहा है। इसी तरह भारतीय इंजीनियरों पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में सुविधाओं की क्या स्थिति है। सुविधायें पुष्ट होगी तो पलायन

भारत सरकार की ट्रंप के प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया को उपरोक्त पृष्ठभूमि में देखना होगा। यदि हमारी संस्थाएं लचर हैं तो एच1बी पर सख्ती हमारे लिए हानिप्रद होगी।

के आभाव में सक्षम भारतीय इंजीनियर भारत में नई कंपनियां लगाऐंगे और भारत को उसी तरह बढ़ाऐंगे जैसे कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की दुकान लगाकर युवा ने किया है। इसके विपरीत एच1बी वीजा पर वही प्रतिबंध भारत के लिए हानिकारक हो जाएगा, यदि सुविधायें कमजोर होगी।

भारत सरकार की ट्रंप के प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया को उपरोक्त पृष्ठभूमि में देखना होगा। यदि हमारी संस्थाएं लचर हैं तो एच1बी पर सख्ती हमारे लिए हानिप्रद होगी। तब हमारे इंजीनियर अमेरिका में रोजगार करके भारत को रेमिटेंस नहीं भेज सकेंगे चूँकि ट्रंप ने एच1बी पर सख्ती की है। वे भारत में कंपनी बनाकर जीवनयापन कर सकेंगे चूँकि न्याय, पुलिस तथा बुनियादी संरचना लचर है। लेकिन यदि हमारी न्याय, पुलिस तथा बुनियादी संरचना उत्कृष्ठ है तो हमारे इंजीनियर भारत में रोजगार करेंगे। ध्यान रहे कि हमारे इंजीनियरों के योगदान से अमरीकी कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ी है। अतः हमारे इंजीनियरों को घर पर ही सही वातावरण मिल जाए तो वे भारत में ही उत्कृष्ठ कंपनियां बनाएंगे जो कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होगी। साथ–साथ अमेरिका को भारतीय इंजीनियर न मिलने से उसकी प्रतिस्पर्धा घटेगी। जिस प्रकार कबड्डी के एक खिलाड़ी के टीम बदलने से प्रतिद्वंदी टीमों का भविष्य बदल जाता है; उसी प्रकार हमारे उत्कृष्ठ इंजीनियरों के घर रहने से हम आगे निकल सकते है।

ट्रंप ने अपनी पॉलिसी का सार्वजनिक एलान कर दिया है और वे इसे लागू कर रहे है। भारत सरकार के सामने दो रास्ते खुले है। एक रास्ता है कि अमेरिका से याचना करें कि एच1बी पर सख्ती न की जाए, भारतीय इंजीनियरों का पलायन होता रहे, अमेरिकी कंपनियाँ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बनी रहें, और हम पीछे पड़े रहें। दूसरा उपाय है कि ट्रंप की पॉलिसी को सकारात्मक ढंग से लें और अपनी न्याय, पुलिस तथा बुनियादी संरचना को चुस्त करें, अपने इंजीनियरों के लिए भारत में धंधा करना आसान बनाएं, भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करे और अमेरिका को पछाड़े। आश्चर्य है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव से अनुनय विनय की है कि एच1बी पर सख्ती न करें। प्रतीत होता है कि भारत सरकार में साहस नहीं है कि अपनी संस्थाओं को ठीक करके भारत को आगे ले जाए। भारत सरकार अपने युवाओं का एक्सपोर्ट करके उनके द्वारा भेजी गई रेमिटेंस पर जीना पसंद कर रही है। ❑❑

किसानों में कुपोषण की कुंजी

ऐसे वक्त में, जब वैश्विक खाद्य भंडार 72.05 करोड़ टन के साथ रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है, एक परेशान करने वाली खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का आकलन है कि पिछले 15 वर्षों में पहली बार भूख का आंकड़ा बढ़ा है। साल 2015 में जहां दुनिया भर में 77.7 करोड़ लोग भूख के शिकार थे, वहीं 2016 में यह संख्या बढ़कर 81.5 करोड़ पहुंच गई। आज हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, मगर घरेलू मोर्चों पर भी हमें कोई उत्साहित करने वाली तस्वीर नहीं दिख रही। इस साल के वैश्विक भूख सूचकांक पर एक निगाह डाल लीजिए। इसमें भारत तीन पायदान नीचे लुढ़का है और हम उत्तर कोरिया से भी पिछड़ गए हैं। 119 देशों के आंकड़ों को मिलाकर तैयार इस सूचकांक में भारत 100वें स्थान पर है और इसे 'गंभीर श्रेणी' में रखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि 'चूंकि दक्षिण एशिया की तीन–चौथाई आबादी भारत में रहती है, इसलिए इस मुल्क में भूख के हालात दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सफलता पर व्यापक असर डालते हैं।'

जाहिर है, भूख से लड़ने के मामले में भारत की इस शर्मनाक तस्वीर ने दक्षिण एशिया को इस मोर्चे पर पीछे धकेल दिया है। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के तमाम देशों का प्रदर्शन इसमें अच्छा दिख रहा है। सूचकांक में पाकिस्तान जहां 106वें पायदान पर है, तो चीन 29वें, नेपाल 72वें, म्यांमार 77वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 88वें स्थान पर है।

एक साल पहले भी भारत इस सूची में 97वें स्थान पर था। तब 118 विकासशील देशों को मिलाकर यह सूचकांक तैयार किया गया था और हम हमेशा की तरह पाकिस्तान को छोड़कर अपने तमाम पड़ोसियों से पीछे थे। 12 साल पहले 2006 में जब पहली बार यह सूची बनी थी, तब भी हमारा स्थान 119 देशों में 97वां था। जाहिर है, 12 साल बाद भी हम जहां थे, वहीं पर खड़े हैं। इस साल जीडीपी विकास दर के कुछ नीचे जाने के दावे किए

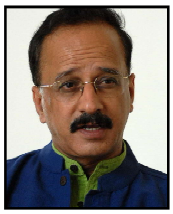

अगर हम चाहते हैं कि 2022 तक देश में को भी भूखा न रहे, तो हमें कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देकर खेती–बाड़ी को फिर से जिंदा करना चाहिए। सच भी यही है कि कृषि क्षेत्र ही 'सबका साथ, सबका विकास' की संकल्पना साकार कर सकता है।

– देविंदर शर्मा

जा रहे हैं, जिसे सरकार महज तात्कालिक गिरावट बता रही है, मगर इन 12 वर्षों में भारत का जीडीपी औसतन 8 फीसदी रहा है, फिर भी देश में भूख की समस्या बढ़ी है। साफ है, तमाम उतार–चढ़ावों के बावजूद देश में भूख की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है।

ज्यादा भूख का मतलब है, ज्यादा कुपोषण। देश में कुपोषण की दर क्या है, इसका अगर अंदाजा लगाना हो, तो लंबाई के हिसाब से बच्चों के वजन का आंकड़ा देख लेना चाहिए। आज देश में 21 फीसदी से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। दुनिया भर में ऐसे महज तीन देश जिबूती, श्रीलंका और दक्षिण सूडान हैं, जहां 20 फीसदी से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। जब किसी देश का 21 फीसदी बचपन कुपोषण से जूझ रहा है, तो किस बुनियाद पर उसके महान आर्थिक भविष्य का दावा किया जा रहा है, यह सोचने का विषय है?

देश की यह बदहाल तस्वीर यहीं नहीं थमती। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो हमें एक ऐसी कटु सच्चाई से रूबरू कराता है, जिसे हम शायद ही जानना चाहेंगे। ग्रामीण भारत का खानपान अब उससे भी कम हो गया है, जैसा 40 वर्ष पहले था। रिपोर्ट के अनुसार, 1975–79 की तुलना में आज औसतन ग्रामीण भारतीय को 500 कैलोरी, 13 ग्राम प्रोटीन, पांच मिलीग्राम आयरन, 250 मिलीग्राम कैल्सियम व करीब 500 मिलीग्राम विटामिन–ए कम मिल रहा है। यह वहीं ग्रामीण भारत है, जहां देश की लगभग 70 फीसदी आबादी बसती है। अगर वहां खाद्य पदार्थों की मात्रा कम हुई है और वे कुपोषण से जूझ रहे हैं, तो यह खतरे की घंटी है। मगर दुखद है कि इस शर्मनाक स्थिति पर कोई बहस करता नहीं दिखता, मीडिया भी नहीं।

इसी तरह, तीन वर्ष से कम उम्र के नौनिहालों को औसतन 80 मिलीलीटर दूध ही रोजाना मिल पाता है, जबकि उन्हें जरूरत 300 मिलीलीटर की है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाइए कि आखिर क्यों उस सर्वे में 35 फीसदी ग्रामीण वयस्क कुपोषित पाए गए और 42 फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन के? क्या यह आधी रात को संसद सत्र बुलाने की ठोस वजह नहीं होनी चाहिए थी?

तीन वर्ष से कम उम्र के नौनिहालों को औसतन 80 मिलीलीटर दूध ही रोजाना मिल पाता है, जबकि उन्हें जरूरत 300 मिलीलीटर की है।

हालांकि ऐसा कुछ करने की बजाय साल 2015 में इस राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो को ही भंग कर दिया गया, जबकि 1972 में अपने गठन के बाद से यह लगातार काम कर रहा था। अपने यहां जहां हर 6 महीने में आर्थिक विकास को मापा जाता है, पोषण संबंधी सर्वे 10 साल में एक बार किए जाते हैं। फिर भी इसके आंकड़े सुखद नहीं आते। ये आंकड़े आर्थिक विकास की हमारी गाथा को दागदार बनाते हैं। लगता है, कुपोषण के आंकड़े आर्थिक विकास के अंकगणित की चमक–दमक में कहीं छिपा दिए गए हैं।

सही है कि भूख से लड़ना एक जटिल व चुनौतीपूर्ण काम है, मगर यह असंभव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे लेकर सोचा नहीं गया। एक के बाद दूसरे प्रधानमंत्री ने भूख से लड़ने की अपनी नेकनीयती दिखाई है। फिर चाहे वह इंदिरा गांधी हों, जिन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया, या मनमोहन सिंह, जिन्होंने कुपोषण को 'राष्ट्रीय शर्म' बताया, या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित बताया है, फिर भी अब तक उपयुक्त आर्थिक नीति नहीं बन सकी है। हमारे नौकरशाह दुर्भाग्य से उस कॉरपोरेट सोच में उलझ गए हैं, जो 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत के चश्मे से गरीबी हटाने की बात कहती है। जबकि बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाकर आर्थिक विकास का सपना देखने वाला यह मॉडल दुनिया भर में विफल माना जाता है।

गरीबी, भूख और कुपोषण से लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती, जब तक कि कृषि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा। एक हालिया अमेरिकी अध्ययन बताता है कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर किए जाने वाले निवेश की तुलना में कृषि में लगाई गई पूंजी गरीबी मिटाने में पांच गुना अधिक प्रभावी होती है। यह वाकई एक उल्लेखनीय नतीजा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्री, नीति–निर्माता और नौकरशाह वैचारिक रूप से बाजार के सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और कृषि व सामाजिक क्षेत्र में निवेश को जानबूझकर कम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2022 तक देश में कोई भी भूखा न रहे, तो हमें कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देकर खेती–बाड़ी को फिर से जिंदा करना चाहिए। सच भी यही है कि कृषि क्षेत्र ही 'सबका साथ, सबका विकास' की संकल्पना साकार कर सकता है। ❑❑

जीएम सरसों का खतरा टलने से राहत

जीएम (जेनेटिकली मोडीफाईड) सरसों को फिलहाल स्वीकृति न देने के केंद्रीय सरकार के फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिली है जो जीएम खाद्य फसलों के विभिन्न दुष्परिणामों के बारे में बहुत चिंतित हैं। पर साथ में यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यह रोक कुछ समय के लिए ही है। कुछ समय बाद अनुमति मिलने की संभावना अभी खुली हुई है। अतः जीएम सरसों व अन्य जीएम फसलों के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में लोगों को सचेत करने के प्रयास जारी रहने चाहिए।

इस संदर्भ में अनेक विख्यात वैज्ञानिकों की राय जानना जरूरी है।

हाल ही में देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ है। वे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर बॉयलाजी हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे तथा नैशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रो. पुष्प भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी) के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया।

प्रो. पुष्प भार्गव ने जेनेटिक रूप से संवर्धित (जेनेटिकली मोडीफाईड) या जीएम फसलों का बहुत स्पष्ट और तथ्य आधारित विरोध किया, एवं वह भी बहुत प्रखरता से।

उन्होंने लिखा, "यदि हम सही विज्ञान के लिए प्रतिबद्ध हैं व अपने नागरिकों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमने जैसे जीएम बैंगन पर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही हमें जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सभी जीएम फसलों को 'नहीं' कह देना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के 17 देशों ने कह दिया है।"

एक अन्य लेख में प्रो. भार्गव ने लिखा कि लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव–जंतुओं व पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है व यह सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा है।

इस विख्यात वैज्ञानिक ने आगे लिखा कि दूसरी ओर जीएम फसलों का समर्थन करने वाले लगभग सभी पेपर या प्रकाशन उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने कान्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्वीकार किया है या जिनकी विश्वसनीयता व ईमानदारी के बारे में सवाल उठ सकते हैं।

प्रायः जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन जीएम फसलों को मिला है पर प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन कर यह स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है।

इस विश्व ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ने देश को चेतावनी दी कि चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों (विशेषकर अमेरिकी) के हितों को जेनेटिक रूप से बदली गई (जीएम) फसलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयासों से सावधान रहे। उन्होंने इस

वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

– भारत डोगरा

चेतावनी में आगे कहा है कि इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि व खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है।

विज्ञान व तकनीक, पर्यावरण व वनों के मंत्रालयों से जुड़ी स्थाई संसदीय समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के 31 संसद सदस्य हैं। इस समिति ने 25 अगस्त 2017 को राज्यसभा अध्यक्ष को 'अपनी नई रिपोर्ट सौंपी जिसका शीर्षक है 'जेनेटिकली मोडीफाईड (जेनेटिक रूप से संवर्धित या जीएम) फसले व पर्यावरण पर उनका असर'।

इस रिपोर्ट में संसद और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि हमारे देश में जीएम फसलों के जो नियमक (रेगुलेटर) हैं, वे प्रायः उस जानकारी के भरोसे बैठे हैं जो जीएम फसलों के प्रसार की अनुमति मांगने वाले उपलब्ध करवाते हैं। समिति ने कहा है कि इस कारण यह संभावना बनी रहती है कि जीएम फसलों की तकनीकी विकसित करने वाले अपनी जरूरतों के अनुसार जानकारी में हेराफेरी करें।

समिति ने विशेषतौर पर इस ओर ध्यान दिलाया है कि संबंधित सरकारी अनुसंधान संस्थानों ने जीएम फसलों के मानव स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के असर को समझने के लिए जरूरी अध्ययन नहीं करवाए हैं जिसके कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य हितों की रक्षा में कठिनाई आ रही है तथा जो जीएम फसल फैलाने से जुड़े स्वार्थ है उनके द्वारा दी गई जानकारी हावी हो जाती है।

संसदीय समिति ने बताया है कि हाल के जीएम सरसों के विवाद में अभी कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका है। अनेक राज्य सरकारें ऐसी फसलों के व्यापारिक प्रसार की स्वीकृति देने के विरुद्ध है।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक हमारे देश में एक ही जीएम फसल को स्वीकृति मिली है व वह है बीटी काटन। संसदीय समिति ने इस बारे में भी सवाल उठाए हैं कि बीटी काटन के कई दुष्परिणामों से ध्यान हटाते हुए सरकार ने बार–बार बीटी कॉटन की सफलता की ही जानकारी देने का प्रयास क्यों किया है, निष्पक्ष जानकारी लोगों के सामने क्यों नहीं रखी है। समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2000–2005 के दौरान देश की कपास की फसल के क्षेत्र में बीटी काटन का स्थान मात्र 6 प्रतिशत था व इस दौरान कपास की उत्पादकता (यील्ड) 69 प्रतिशत बढ़ी। दूसरी ओर वर्ष 2005–15 के दौरान बीटी कॉटन का क्षेत्र तेजी से बढ़ते हुए 94 प्रतिशत तक भी पहुंच गया था, पर इस दौरान उत्पादकता वृद्धि मात्र 10 प्रतिशत दर्ज हुई।

जीएम फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

समिति के कहा है कि जब जीएम फसलों का 90 प्रतिशत हिस्सा मात्र 6 देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेन्टीना, ब्राजील, भारत, चीन) तक सीमित है तो सरकार यह जानने का प्रयास क्यों नहीं करती है कि अधिकांश देशों ने इन्हें अपनाने से क्यों इंकार किया है।

जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि यह फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साईंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच) ने बहुत सारगर्भित ढ़ंग से व्यक्त किया है। इस पैनल में एकत्र हुए विश्व के अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है – "जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं व यह फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रही हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जीएम फसलों व गैर जीएम फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्त्ति नहीं हो सकती है, जिसे फिर ठीक नहीं दिया जा सकता है। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए।"

इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व बहुत दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्त्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ❑❑

वामपंथ से कोसो दूर देशभक्ति

भारत में वामपंथियों की सोच राष्ट्रीय भावनाओं से अलग ही नहीं उसके एकदम विरूद्ध रही है। वामपंथ की राजनीति एवं उनके दलीय संगठनात्मक ढांचे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया के कमोबेश सभी लोकतांत्रिक देशों की जनता ने वामपंथी दलों एवं उनकी विचारधारा को लोकतंत्र के अनुकूल नहीं मानते हुए, सिरे से नकार दिया है। यानी दो टूक कहें तो जहां भी लोकतंत्र की सुगंध आई वहां से वामपंथी काफूर कर दिए गए। भारतीय लोकतंत्र में भी आज वामपंथी दलों का जनप्रतिनिधित्व और जनादेश में भागीदारी नगण्य ही है। जबकि यह भी एक तथ्य है कि इसी 'सहिष्णु' देश भारत ने दुनिया में पहली बार वामपंथियों को लोकतांत्रिक ढंग से राजनीति करने और सत्ता (केरल में) तक पहुंचने का पहला अवसर दिया था। यह अलग बात है कि अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से वे लोकतंत्र के माहौल में खुद कसे फिट नहीं कर पाए। जनादेश के पैमाने पर बुरी तरह पिट चुकी वामपंथी दलों की राजनीतिक हैसियत का प्रमाण यही है कि जहां केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है वहीं उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में आज कोई उनका नामलेवा नहीं है। भारत के सभी पांच–छः राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच वामदलों की स्थिति बेहद कमजोर नजर आती है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के विरूद्ध वामपंथी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को 'तोजो का कुत्ता' वामपंथियों ने ही कहा था। मुस्लिम लीग की देश विभाजन की मांग की वकालत वामपंथी ही कर रहे थे। अंग्रेजों के समय से सत्ता में भागीदारी पाने के लिए वे राष्ट्र विरोधी मानसिकता का विषवमन सदैव करते रहे हैं। वामपंथियों ने महात्मा गांधी को 'खलनायक' और मोहम्मद अली जिन्ना को 'नायक' की उपाधि दी थी। खंडित भारत को स्वतंत्रता मिलते ही वामपंथियों ने हैदराबाद के निजाम के लिए लड़ रहे मुस्लिम रजाकारों की मदद से अपने लिए स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बनाने की कोशिश की। 24 मार्च, 1943 को भारत के अतिरिक्त गृह सचिव रिचर्ड टोटनहम ने टिप्पणी लिखी कि 'भारतीय कम्युनिस्टों का चरित्र ऐसा है कि वे किसी का विरोध तो कर सकते हैं, किसी के सगे नहीं हो सकते, सिवाय अपने स्वार्थों के।'

आज स्थिति बदल रही है। जनादेश का मिजाज बदल रहा है। कांग्रेस अपने पापों की सजा भुगतने को अभिशप्त है। अतः जेएनयू में भी बदलाव स्वाभाविक है। जेएनयू में अब दूसरी विचारधाराएं भी स्थापित होने लगी हैं।

– आशीष रावत

भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी और उनकी कांग्रेस को ब्रिटिश दासता के विरूद्ध भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे देशभक्तों पर वामपंथियों ने 'देशद्रोही' का ठप्पा लगाया। चीन को अपना आदर्श मानने वाली कथित लोकतंत्रात्क पार्टी मार्क्सवादी काम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय काम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एक ही आका के दो गुर्गे हैं। भले ही चीन भारत के खिलाफ कूटनीतिक युद्ध लड़ रहा हो लेकिन इन दोनों साम्यवादी धड़ों का मानना है कि चीन भारत का शुभचिंतक है लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का नम्बर एक दुश्मन। देश के सबसे बड़े साम्यवादी संगठन के नेता कामरेड प्रकाश करात ने चीन के बनिस्पत देश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्यादा खतरनाक बताया है। अपनी पार्टी के मुखपत्र

पीपुल्स डेमोक्रेसी के एक अंक में उन्होंने लिखा था कि देश के कॉरपोरेट मीडया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया के हथियार एजेंट और संघ के गठजोड़ के कारण चीन के साथ भारत का गतिरोध दिखाई दे रहा है। संत लक्ष्मणानंद की हत्या कम्युनिस्टों और ईसाई मिशनरी गठजोड़ का प्रमाण थी। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छातीसगढ़ और त्रिपुरा में यानी जहां भी साम्यवादी हावी हैं वहां इनके लक्ष्य में राष्ट्रवादी हैं और संघ कार्यकर्ताओं की हत्या इनके एजेंडे में शमिल है। पेकिंग को साम्यवादी मक्का और चीन को साम्यवादी शक्ति का केंद्र मानने वाले प्रकाश करात अपने आलेख में लिखते हैं कि पश्चिमी देश संघ के माध्यम से षड्यंत्र कर भारत को चीन के साथ लड़ाना चाहता है। वामपंथी दलों में आंतरिक कलह, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा, पश्चिम बंगाल में राशन के लिए दंगा, देश की लगभग हर मुसीबत में विपरीत बातें करना, चरम पर भ्रष्टाचार, देशविरोधी हरकतें, विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या जैसे वाकयों को लेकर वामपंथ बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया से धीरे–धीरे समाप्त होने के बाद अब इनका दमनकारी शासन केवल चीन में बचा रह गया है और अब यह भारत में भी अंतिम सांसें ले रहा है।

दुनिया में कम्युनिस्टों के बुरे हश्र का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि महज नौ सीटों वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के बीच सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। अर्थात, भारत में जिसकी हैसियत किसी गिनती में नहीं वो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर सभी गैरलोकतांत्रिक देशों को भी मिलाकर पूरी दुनिया की बात करें तो माकपा से बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है। परस्पर विरोधाभास भरा ये तथ्य दुनिया के तमाम वामपंथी दलों की दुर्दशा का साफ चित्रण करता है। लोकतांत्रिक देशों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की लोकसभा की कुल 543 सीटों में से महज नौ सीटें हैं। वहीं भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की लोकसभा में महज एक सीट है। अब चूंकि जनता के बीच की राजनीति से वामपंथी लगभग खारिज हो चुके हैं तो इनका बौद्धिक ठौर–ठिकाना जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय बचा है। देश की राजधानी के इसी ठिकाने से वामपंथी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी राजनीति कर लेना चाहते हैं। यह ठिकाना इनको साठ के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस (इंदिरा) द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था। चूंकि जेएनयू की स्थापना के पीछे उसे वाम अखाड़ा बनाने की सुनियोजित साजिश जेएनयू की स्थापना के बाद की तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार द्वारा रची गई थी। सत्ता पोषित सुविधाभोग और विलासी जीवन पद्धति जेएनयू को विरासत में मिली। बौद्धिक मोर्चे पर कांग्रेस के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जेएनयू नामक इस प्रकल्प को स्थापित किया। अब सवाल है कि आखिर दिल्ली जैसी जगह जहां एक वामपंथी विधायक तक की राजनीतिक हैसियत नहीं बन पाई है, वहां जेएनयू का यह किला 'लाल–सलाम' के नारों से दशकों तक कैसे अभेद्द बना रहा है? इस सवाल का जवाब साठ के दशक के उत्तरार्ध एवं सत्तर के दशक की शुरुआत में जाने पर मिल जाता है। दरअसल यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी खुद के लिए ही कांग्रेस में महफूज नहीं महसूस कर रहीं थीं। कांग्रेस में विरोधी खेमा सिंडिकेट–इन्डिकेट के रूप में कमर कसने लगा था। गैर–कांग्रेसवाद का असर देश में यों चला कि साठ के दशक में ही देश के दस राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी। साठ के दशक के अंतिम दौर में कांग्रेस में इंदिरा के लिए ऐसी स्थिति तक आ गई कि उन्हें सरकार चलाने के लिए वामपंथियों की मदद लेनी पड़ी और इसके एवज में कम्युनिस्टों ने भी अकादामिक संस्थाओं पर कब्जा करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ जनसंघ आदि का विस्तार भी देश में होने लगा था। वोट अब बैंक की शक्ल में आसानी से कांग्रेस के झोले में जाता नहीं दिख रहा था। परिणामतः इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म बनाम साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर भरोसा दिखाया। हालांकि हिन्दुत्व की राजनीति के जवाब में सांप्रदायिकता का विमर्श तो इंदिरा देश में चलाना चाहती थीं लेकिन यह काम वो सीधे कांग्रेस की बजाय कुछ अन्य चेहरों के भरोसे करना चाहती थीं। चूंकि इंदिरा को इस बात का डर जरूर रहा होगा कि यदि हिन्दुत्व को साम्प्रदायिकता के तौर पर प्रचारित करने का काम खुद कांग्रेस करने लगेगी तो कहीं हिन्दू ध्रुवीकरण कांग्रेस के खिलाफ न हो जाए।

आज स्थिति बदल रही है। जनादेश का मिजाज बदल रहा है। कांग्रेस अपने पापों की सजा भुगतने को अभिशप्त है। अतः जेएनयू में भी बदलाव स्वाभाविक है। जेएनयू में अब दूसरी विचारधाराएं भी स्थापित होने लगी हैं। विचारधारा थोपने का रोना रोने वाले वामपंथी यह क्यों नहीं बताते कि आखिर इन पांच दशकों में जेएनयू में वैचारिक प्रतिनिधित्व के नाम पर किसी एक विचारधारा का कब्जा क्यों रहा है? जिस दिल्ली में वे एक पार्षद नहीं बना पाते वहां वे जेएनयू कैंपस में किस जनाधार पर कब्जा किए बैठे रहे हैं? इस लिहाज से देखें तो लोकतांत्रिक दुनिया सहित समूचे देश से बेघर हो रहे वामपंथियों के लिए जेएनयू किसी 'रैन–बसेरा' से कम नहीं है। ❑❑

भारतीयता के अनुरूप हो शिक्षा व्यवस्था

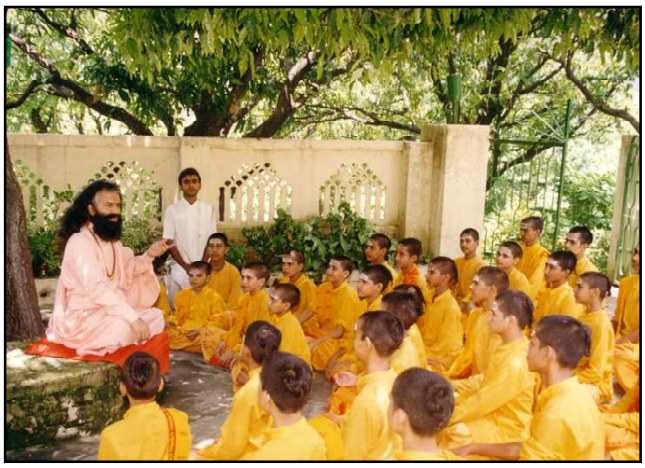

आज भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था के रूप में पुनः स्थापित करने के लिये आधुनिक तकनीकी, विज्ञान और जीवन के सत्य को उजागर करने तथा मानवीय जीवन मूल्यों का बोध कराने वाली शिक्षा व्यवस्था निर्मित करने की आवश्यकता है। भारत में 300 वर्षों से गहरी जड़ें जमा चुकी ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था से मुक्त होकर नयी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हमारे समक्ष एक चुनौती है।

ब्रिटिश कार्यालयों में भारतीय नौकरशाह तैयार करने तथा कल–कारखानों में काम करने के लिये भारतीय मजदूर प्राप्त हो सके, इसके लिए मैकॉले ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत को दी, उसका अनुकरण करते हुए, भारत के अपार मानव संसाधन की कौशल व अन्वेषण क्षमता समाप्त होती गयी। शिक्षा द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त करने की मैकॉले की नीति आज भी साकार होती दिखाई देती है। वर्तमान भारतीय शिक्षा द्वारा उत्पन्न सर्वोच्च प्रतिभाओं का उपयोग आज भारत में तथा विदेशों में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये ही काम करने तक सीमित रह गया है।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास प्रारंभ हुए। इनमें 1948–49 में राधाकृष्णनन आयोग, 1952–53 में मुदलियार आयोग, 1964–66 में कोठारी आयोग तथा 1968 में दी गई शिक्षा नीति द्वारा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के पुर्ननिर्माण का प्रयास किया गया।

– डॉ. रेखा भट्ट

ब्रिटिश काल में स्थापित कॉन्वेंट और मिशनरी शिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा एवं अंग्रेजी जीवन शैली के प्रति आमजन का झुकाव देखते हुए, स्वतंत्र भारत में क्रिश्चियन नाम देकर अंग्रेजी माध्यम के अनेक निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के बाद भारत में मैकॉले शिक्षा के कारण स्थापित अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभुत्व को निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा लाभ कमाने का माध्यम बना लिया गया है। इनमें अंग्रेजी में उच्च स्तरीय शिक्षा के नाम पर ऊँची फीस ली जाने लगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम में सामान्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा महंगें निजी व अंग्रेजी माध्यम के शिक्षण संस्थानों में पढ़ना सम्पन्नता व विद्ववता का परिचायक बन गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर निजी व सरकारी शिक्षण संस्थाओं में समाज का श्रेणीगत आर्थिक विभाजन कर मैकॉले की भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की दूरगामी विद्वेषपूर्ण नीति आज भी साकार हो रही है।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास प्रारंभ हुए। इनमें 1948–49 में राधाकृष्णनन आयोग, 1952–53 में मुदलियार आयोग, 1964–66 में कोठारी आयोग तथा 1968 में दी गई शिक्षा नीति द्वारा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के पुर्ननिर्माण का प्रयास किया गया। 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का गठन कर शिक्षा का दस वर्षीय कार्यक्रम तय किया गया। 1986 में सभी वर्गों के विचारों को सम्मिलित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई। 30 वर्ष बाद 2017 में पुनः शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। यह शिक्षा नीति इनक्ल्युसिव एजुकेशन तथा शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर आधारित होगी। लगभग सभी आयोगों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में अर्थव्यवस्था सुधारने, ग्रामीण विकास, आध्यात्मिक विकास, भारतीय

परंपराओं और मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्यों की सिफारिश की गई है। परंतु आजादी के 70 वर्षों बाद भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र का सामाजिक–आर्थिक विकास करने एवं आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देने का शक्तिशाली माध्यम नहीं बन सकी है।

वैश्विक परिदृश्य में आज भारत आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ता नजर आता है, किन्तु इसमें शिक्षा का योगदान, व्यवस्था के क्रियांवयन एवं गतिशीलता की कमियों के कारण न्यूनतम बना हुआ है। समुचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों और युवा शक्ति से संपन्न देश होते हुए भी भारत आज ज्ञान संपन्न देश नहीं बन सका है। सिंगापुर, स्विजरलैंड, ऐसे छोटे देश है जो संसाधन संपन्न नहीं थे किंतु ज्ञान संपन्न बने और आज सबसे विकसित साधन संपन्न देश बन गये है। जापान अनेक प्राकृतिक आपदाओं और विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी ज्ञान संपन्न देश बना। परमाणु विभिषिका को झेल चुका आज का जापान अपने ज्ञान, तकनीक के आधार पर भारत को सभी क्षेत्रों में सहायता देने की क्षमता रखता है। आज से 50 वर्ष पहले तक शिक्षा के क्षेत्र में भारत चीन से बहुत आगे था किंतु आज शिक्षा के क्षेत्र में चीन के कई विश्वविद्यालय पीआईएसए विश्व रैंकिंग में अपना स्थान बना चुके है जबकि भारत का एक भी शिक्षण संस्थान अपना नाम दर्ज नहीं करवा सका है। दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे छोटे–छोटे देश अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा व मूल्यों के आधार पर विश्व की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने वाले देश बन गये है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने के लिये शिक्षण को सैद्धांतिक के साथ सीखने पर आधारित (Learning based) बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये पाठ्य पुस्तकों में लर्निंग कंटेंट (सीखने की सामग्री) व तकनीकी उपलब्ध करवायी जानी चाहिये। पाठ्यक्रम में औपचारिक एवं नियमित शिक्षण में ज्ञान, विज्ञान के साथ भारतीय साहित्य, भारत का इतिहास एवं मानविकी विषयों को समान रूप से प्रोत्साहन मिले। अनौपचारिक शिक्षण के कुछ कालांश निर्धारित कर भारतीय कला, शिल्प जैसी अनेक विधाएँ सिखाने से, विलुप्त होती संस्कृति बचेगी, साथ ही सामाजिक कार्यों के माध्यम से मानवीय मूल्यों का संवर्धन होगा। उनमें अपने परिवेश को देखकर भारतीय समाज की पृष्ठभूमि ज्ञात होगी। उनमें स्वालंबन, परिश्रम, ईमानदारी, निष्ठा जैसे जीवन मूल्यों का संचरण होगा। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं कार्यशालाएँ, सहयोग द्वारा काम करने व राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित करने में अधिक महत्वपूर्ण होगी। ऐसे रचनात्मक प्रयोगों से गांधी आश्रम व टैगोर के शांति निकेतन को प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय में पुनः जीवंत किया जा सकेगा। रचनात्मकता से जुड़े विषयों को सभी स्थानों पर समान रूप से हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सिखाया जाये। इस तरह भाषायी असमानता व विद्वेष समाप्त कर शिक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होगा। इनसे विधार्थी व शिक्षक दोनों को रूचि अनुसार सीखने की नई तकनीकें जानने व कार्य के अनुभव को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

सीखने व जानकारी प्राप्त करने के लिये शिक्षा व्यवस्था में औपचारिक शिक्षा का प्रावधान है। जानकारियों को स्मरण रखने की क्षमता और सीखने की दक्षता के मूल्यांकन के लिये दी गई परीक्षा पद्धति इस प्रक्रिया को विद्यार्थी के लिये तनावग्रस्त बनाती है। इससे विद्यार्थी द्वारा विषय को आत्मसात करने तथा आचरण में सम्मिलित करने जैसे शिक्षा के मूल उद्देश्य समाप्त हो जाते है। विदेशी परीक्षा प्रणाली जैसे CBCS (Choice based credit system) में आंशिक रूप से ग्रेड पॉईंट देने की व्यवस्था तो अपनायी जाती है किन्तु मूल्यांकन का आधार तथा सत्र पर्यंत शैक्षणिक प्रदर्शन में धीरे–धीरे सुधार के अवसर प्रदान कर शिक्षा व्यवस्था को तनावमुक्त बनाने की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के विशाल समूह तथा तकनीकी साधनों के अभाव में अपनाया जाना संभव नहीं होता।

भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा का डिजीटलीकरण करने को ही उसकी श्रेष्ठता का मापदंड नहीं बनाया जा सकता। पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में खोले जाने वाले विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या बढ़ी है किन्तु उनमें मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। निवेश के लिये निजी कंपनियों से आर्थिक सहायता ली जा सकती है किन्तु संसाधन उपलब्ध करवाना, शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निरीक्षण व उनमें परिणामों की समीक्षा आदि की जवाबदेही सरकार द्वारा ही सुनिश्चित की जाये अन्यथा शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से निजी क्षेत्रों को सौंपने से शिक्षा का व्यापारीकरण होगा तथा सामान्य जन शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से वंचित रह जायेगा।

यदि भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीयता की आत्मा और संस्कृति के अनुरूप शिक्षण की अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना और विकास किया जायेगा तभी सन् 2027 में जब भारत विश्व का सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रथम देश होगा तब देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति का शत–प्रतिशत योगदान प्राप्त हो सकेगा। भारत अपनी ज्ञान आधारित मूल शिक्षा के आधार पर विश्व मानवता को नई दिशा देने में सक्षम होगा। ❑❑

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (7 नवंबर)

कैंसर से जंग की नई उम्मीदें

हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में इस बीमारी और दर्द से लड़ने वालों को जागरूक करना है। इसके जरिये यह संदेश भी दिया जाता है कि कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का सामना करने वाले लोगों को दवाईयों और नये तरीके के उपचार के बारे में बताकर बड़े पैमाने पर उनकी मदद की जा सकती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और दवाओं ने कई असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त कर ली है और कुछ को रोक दिया है। लेकिन खतरनाक कैंसर सभी चिकित्सा विधियों को चकमा देकर आगे बढ़ने वाला रोग साबित हुआ है। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गयी है। भारत में कैंसर दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है जो हर साल 11 फीसदी की दर से बढ़ रही है। सन 2001 में देश में विभिन्न प्रकार के कैंसर के 8 लाख मरीज थे, अब इनकी संख्या 25 लाख के ऊपर पहुंच रही है। हर साल लगभग पांच लाख लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं। शरीर में विष बेल की तरह जिस तेजी से फैलने वाली यह बीमारी बढ़ रही है, वहीं इससे लड़ने और इस पर विजय पाने के चिकित्सीय उपाय भी दुनिया भर में हो रहे हैं।

कैंसर के मोर्चे पर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएस रिसर्च सेंटर कोलकाता के वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थों की पोषक ऊर्जा से उस औषधि को तैयार कर लिया है जो कैंसर कोशिकाओं पर लगाम लगाकर उसका उन्मूलन करने में सक्षम है।

– निरंकार सिंह

भारत सहित दस देशों के वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमें कैंसर के जीनों के रहस्य जानने में जुटी हैं। इस कड़ी में ब्रिटिश टीम स्तन कैंसर, जापानी लिवर कैंसर और भारतीय टीम मुंह के कैंसर की जीनों का कैटलाग बनाने में जुटी है। इसके अलावा चीनी वैज्ञानिक पेट, तो अमेरिकी मस्तिष्क, गर्भाशय और पेंक्रियाज के कैंसर जीनों को डीकोड कर रही हैं। इन वैज्ञानिकों का दावा है कैंसर जीनों के संपूर्ण कैटलाग को तैयार करने में कम से कम पांच साल और लगेंगे। फिलहाल ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कैंसर की दो सबसे खतरनाक किस्मों– त्वचा और फेफड़ों के जेनेटिक कोड को तोड़ दिया है। इस खोज को कैंसर से लड़ने की दिशा में क्रांतिकारी उपलब्धि माना जा रहा है। ताजा सफलता कैंब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को मिली है, जिन्होंने त्वचा और फेफड़े के कैंसर के परिणामस्वरूप डीएनए में होने वाले बदलाव का खाका तैयार किया है। कंस्टोरियम की ब्रिटिश टीम के नेता मिशेल स्ट्राट्न के मुताबिक, 'कैंसर कैटलाग इस बीमारी के बारे में हमारे समूचे नजरिए को बदल देंगे।' सभी कैंसर जीनों को डीकोड करने के बाद ऐसी विशिष्ट दवाएँ तैयार कर पाना आसान हो जायेगा।

कैंसर के मोर्चे पर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएस रिसर्च सेंटर कोलकाता के वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थो की पोषक ऊर्जा से उस औषधि को तैयार कर लिया है जो कैंसर कोशिकाओं पर लगाम लगाकर उसका उन्मूलन करने में सक्षम है। वैज्ञानिक परीक्षणों में भी इस औषधि के नतीजे बेहतर पाये गये हैं। कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के नैदानिक अनुसंधान केंद्र (सीआरसी) के निदेशक डॉ. टी.के. चटर्जी के अनुसार– 'डीएस रिसर्च सेंटर की पोषक ऊर्जा से तैयार की गई औषधि सर्वपिष्टी के पशुओं

पर किये गये परीक्षण के परिणाम उत्साहजनक पाये गये हैं। यदि पशुओं के शरीर पर सर्वपिष्टी का प्रयोग किये जाने के बाद सीआरसी ने उत्साहजनक परिणाम प्राप्त किये हैं तो ऐसे ही परिणाम इसे मानव शरीर पर प्रयोग करने से भी प्राप्त किये जा सकते हैं, जो कैंसर उपचार के इतिहास में युगांतकारी घटना होगी।

सीआरसी विभिन्न रोगों के लिए दवाईयों का नैदानिक परीक्षण करता है। इसी सिलसिले में उन्होंने सर्वपिष्टी का भी नैदानिक परीक्षण किया था। किसी दवाई की प्रभावकारिता का स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो प्रकार का परीक्षण किया जाता है– पहला, औषधीय (फार्माकोलॉजिकल) परीक्षण और दूसरा, विष विद्या संबंधी (टोक्सीकोलॉजिकल) परीक्षण। ये परीक्षण आयातित सफेद चूहों पर किये गये। पशु शरीर में कैंसर कोशिकाओं को प्रविष्ट कराया गया और जब ट्यूमर निर्मित हो गया तब हमने दवा देना शुरू किया। 'पोषक ऊर्जा' के परीक्षण की स्थिति में 14 दिनों बाद जो प्रतिक्रियायें देखी गयीं, उनमें कोशिकाओं की संख्या स्पष्ट रूप से कम होना शुरू हो गई थी। पशु शरीर में कोई अल्सर पैदा नहीं हुआ। ट्यूमर विकास दर 46 प्रतिशत तक कम हो गई थी और दवाई की विषाक्तता लगभग शून्य थी। ऐसे सकारात्मक परिणाम हाल के समय में नहीं देखे गये थे। इस औषधि में कैंसर को रोकने और उससे लड़ने की अपरिमित संभावनाएं हैं।'

औषधियों के परिणाम–परीक्षण की एक सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति है। औषधियां प्रायः विषों और ड्रगों से बनती है अतएवं पहला परीक्षण किया जाता है कि वे स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में तो नहीं डाल देगी। लेकिन डीएस रिसर्च सेंटर ने तो मानवीय भोज्य पदार्थों में सन्निहित पोषक ऊर्जा को प्राप्त करके औषधियां तैयार की थी इसलिए वे औषधियां मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वथा अनुकूल थी। यहां तक कि औषधि के सेवन का माध्यम भी दुग्ध शर्करा को बनाया गया था जो एक मानवीय भोज्य है और स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। सन् 1982 में सेंटर ने कैंसर की औषधि तैयार की। इस औषधि के परीक्षण के लिए प्रारंभ से ही नीति बनी कि केवल ऐसे रोगियों की तलाश की जाए जिन्हें अस्पताली चिकित्सा के धर्मकांटे ने चिकित्सा के लिए अयोग्य मानकर अंतिम रूप से छोड़ दिया हो। खोजबीन करके इस तरह के रोगियों तक पोषक ऊर्जा की खुराकें पहुंचायी जाने लगी। उन्हें यह भी कह दिया गया कि अपने कष्टों के लिए और स्वास्थ्य के विकास के लिए जो भी औषधियां वे लेते रहे हैं उन्हें लेते रहें। सेंटर के वैज्ञानिक डा. उमाशंकर तिवारी के निर्देशन में परीक्षण अभियान शुरू हुआ। अंततः औषधि की सफलता और उसके प्रभाव–परिणाम की सकारात्मकता, रोगियों के अपने अनुभवों तक सीमित नहीं रही, वह जांच रिपोर्टो से भी प्रमाणित हुई और पारंपरिक चिकित्सा के वर्तमान सूत्रपातों को अक्सर विस्मित भी करती रही।

डा. चटर्जी के परीक्षण से यह साबित हो गया है कि यह औषधि कैंसर रोगियों के लिए बहुत कारगर है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस सफलता की सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को भेजी गई है। अब तक 926 रोगियों की सूचना डब्ल्यूएचओ को उनके सभी विवरण और उपचार प्रलेखों के साथ तीन चरणों में भेजी गई है। सूची में उन रोगियों के नाम शामिल हैं जो कभी मस्तिष्क, अग्राशय, यकृत, रक्त, गर्भाशय, स्तन लगभग सभी प्रकारों के कैंसर से पीड़ित रह चुके हैं– और अब सामान्य और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। इस औषधि के बारे में दुनिया को पता तब चला जब उसने भारतीय मूल के अमेरिकी कैंसर वैज्ञानिक के ही कैंसर से ग्रस्त हो जाने पर उनका इलाज हुआ। न्यूयार्क हास्पिटल मेडिकल सेंटर आफ क्वींस के रेडिएशन आंकोलाजी के क्लीनिकल डाइरेक्टर तथा वेल मेडिकल कालेज आफ कोरनेल यूनिवर्सिटी के रेडिएशन आंकोलाजी के एसोसिएट प्रोफेसर डा0 सुह्रद पारिख ने कैंसर से ठीक होने के बाद इस औषधि पर चर्चा के लिए मुंबई के जुहू स्थित होटल सी प्रिंसेस में एक समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में मुंबई के कई अस्पतालों के कैंसर विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वाराणसी के डीएस रिसर्च सेंटर के प्रमुख वैज्ञानिक प्रो. शिवाशंकर को खासतौर से बुलाया गया। तमाम जीते जागते प्रमाणों के बावजूद आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुडा कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं था कि जिस कैंसर पर विजय पाने में पूरी दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक असफल ही रहे हैं, उस पर विशुद्ध भारतीय पद्धति से विजय पायी जा चुकी है।

कुल मिलाकर कैंसर के रोगी को यदि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सुविधाएं और सर्वपिष्टी मिल जाए तो उसकी जान बचायी जा सकती है। लेकिन अभी यह औषधि बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक अशोक कुमार त्रिवेदी का कहना है कि यदि पोषक ऊर्जा विज्ञान के अंतर्गत विकसित की गयी औषधि 'सर्वपिष्टी' को संसार के कैंसर रोगियों की चिकित्सा में समय से लागू कर दिया जाये तो दो से तीन वर्षो के अंदर ही कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या आधी की जा सकती है और पांच से छह वर्षों के भीतर इन मौतों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है।' ❑❑

(लेखक हिन्दी विश्वकोश के सहायक संपादक रह चुके हैं। आज कल स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं।)

अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर लगेगा 28% टैक्स

असम के गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी कैटेगरी की 50 वस्तुओं को ही रखने का फैसला किया गया।

सस्ताः सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।

सस्ता नहींः पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।

पर्दे के पीछे भारत–चीन की लड़ाई

भारत और चीन के बीच डोकलाम मसले का भले ही शांतिपूर्ण हल निकाला लिया गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे एक वॉर चल रही है।

यह वॉर ट्रेड के फील्ड में चल रही है और भारत अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी को लगातार चैलेंज दे रहा है।

डोकलाम विवाद शुरू होने से लेकर अब तक भारत ने जो कदम उठाए हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है। भारत ने अपने देश में चीनी आइटम्स को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, इससे चीन को निश्चित तौर पर तकलीफ हो सकती है। इस वॉर में ड्रैगन को मात खानी पड़ रही है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, चीन को इससे बड़ा नुकसान उठान पड़ सकता है और भारत को किए जाने वाले उसके कुल एक्सपोर्ट में भी कमी आ सकती है।

RBI, SMS द्वारा जनता को करेगा जागरुक

रिजर्व बैंक धोखेबाजों के फर्जीवाड़े और जालसाजी से लोगों को बचाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ेगा। केंद्रीय बैंक 'सुनो आरबीआई क्या कहता है' अभियान के तहत एसएमएस भेजकर आम आदमी को जागरूक करेगा।

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार और चिट फंड योजनाओं में बढ़ते फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को लेकर यह कदम उठाया है। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कॉल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने और ठगने की घटनाएं बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक जल्द ही एक जनजागरण अभियान शुरू करेगा। इसमें एसएमएस के माध्यम से लोगों को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न बैंकिंग कानूनों के प्रति जागरूक करेगा। रिजर्व बैंक 'आरबीआई से' (आरबीआई कहे) पहचान के साथ यह संदेश भेजेगा। केंद्रीय बैंक पहली बार लोगों को जागरूक करने के लिए उसी माध्यम का उपयोग कर रहा है जिसका उपयोग धोखेबाज ठगने के लिए करते हैं।

रिजर्व बैंक के अनुसार, लोग 8691960000 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर फर्जी कॉलों या ई मेल की सच्चाई जान सकते हैं। इसमें आईवीआर सिस्टम के जरिये मदद की जाएगी। इस पर आम आदमी को निवेश के सुरक्षित विकल्पों की जानकारी के साथ चिट फंड के जोखिम को लेकर सावधान किया जाएगा।

नोटबंदी का प्रभाव

नोटबंदी मोदी सरकार की ओर से लिया गया ऐसा कदम था, जिसकी चर्चा आने वाले कई दशकों तक होगी। अब भी इस बात को लेकर बहस जारी है कि आखिर इससे देश को क्या मिला। विपक्ष का अब भी दावा है कि नोटबंदी मोदी सरकार का बेतुका फैसला था, इसके चलते लोगों को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ा।

जीडीपी ग्रोथः जीडीपी ग्रोथ में जबरदस्त कमी देखी गई। 7 फीसदी से ऊपर चल रही ग्रोथ, 6 महीने में 6 फीसदी के नीचे आ गई। नोटबंदी खत्म होने के बाद शुरू हुए जनवरी–मार्च क्वार्टर में यह 6.1 फीसदी पर आ गई, जो 2.5 साल का सबसे लो–लेवल था। वहीं जून क्वार्टर में इसका और बुरा हाल रहा और यह 5.7 फीसदी पर आ गई जो 3 साल का निचला स्तर था।

महंगाईः नोटबंदी के चलते जरूरी चीजों की राशनिंग अपने आप रुकी। इसी का परिणाम रहा कि महंगाई अपने 5 साल के निचले लेवल पर पहुंची। अगस्त में आए महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक, सब्जियों, दालों आदि फूड

वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते रिटेल इनफ्लेशन (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई) 2012 के बाद के निचले स्तर पर आ गई। मई में रिटेल महंगाई 2.18 प्रतिशत रही, जबकि अप्रैल में यह 2.99 प्रतिशत थी। अगस्त में यह 3.36 फीसदी पर रही।

ब्लैकमनी: सरकार ने नोटबंदी से सिस्टम में रहे कुल कैश का लगभग 86 प्रतिशत बैन कर दिया था। सरकार का दावा था कि इस कैश में बड़ी मात्रा ब्लैकमनी की है। इसलिए सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि इस कैश का काफी बड़ा हिस्सा सिस्टम में वापस नहीं आएगा और बेकार हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि नोटबंदी से पहले (8 नवंबर 2016) देश में 500–1000 के पुराने नोटों के तौर पर 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चल रहे थे, जिसमें से 15.28 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट (30 जून 2017 तक) वापस आ गए हैं। इस तरह करीब 99 फीसदी स्क्रैप करंसी सिस्टम में वापस आ गई। इस तरह, ब्लैकमनी कितनी खत्म हुई, यह आंकड़ों से साफ है।

जॉब: Centre for Monitoring Indian Economy के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान 15 लाख लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है।

टैक्स बेस: नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफे के तौर पर सामने आया है। इनकम टैक्स के ताजा अंकाड़ों के मुताबिक, इस बार 5 अगस्त तक 2.83 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2016–17 की समान अवधि में सिर्फ 2.26 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे। इस तरह से इस बार रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 24.7 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो अपने आप में रिकॉर्ड रहा।

टेरर फंडिंग: कश्मीर में हिंसा के लिए आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए फंडिंग का शक होने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा हुर्रियत, अलगाववादी नेताओं और उनके रिश्तेदारों पर जांच का शिकंजा कसा गया। इस मामले में केस भी दर्ज किए गए। शुरू हुई जांच में हुर्रियत नेताओं और कश्मीर के कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

डिजिटल ट्रांजैक्शन: हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल के दौरान डिजिटल ट्रांजेक्शन में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नोटबंदी के चलते मोबाइल वॉलेट पेमेंट सिस्टम से जुड़ी इंडस्ट्री देश में तेजी के साथ डेवलप हुई।

शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 5 भारतीय

फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 5 भारतीय शामिल हैं। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं। वहीं भारतीय महिलाओं की सूची में आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर सबसे ऊपर हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार टॉप 100 में जगह बनाई है। आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर 32वें और एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान पर काबिज हैं। बायोकॉन की संस्थापक चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं। एक सौ लोगों की इस सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं। सूची में पेप्सिको की सीईओ भारतीय मूल की इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर और भारतीय अमेरिकी निक्की हैले ने 43वें स्थान पर कब्जा किया है।

फोर्ब्स की इस सूची में जर्मन चांसलर मर्केल लगातार सातवीं बार पहले स्थान पर कायम रही हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 12 बार इस सूची में पहला स्थान पाया है। मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे दूसरे स्थान पर हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरपर्सन मिलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर काबिज हैं। सूची में फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप को सूची में 19वां स्थान दिया गया है। यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है।

पेंशन योजना की उम्र अब 65 साल

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने की अधिकतम उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। अब 65 साल की उम्र तक के लोग पेंशन योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही 70 साल तक की उम्र तक इसे जारी

रख सकते हैं।

60 से अधिक उम्र में एनपीएस से जुड़ने वाले खाताधारक के पास भी पेंशन कोष और निवेश के लिए वही विकल्प होंगे जो 60 वर्ष की उम्र से पहले एनपीएस से जुड़ने वालों को मिलते हैं। इसमें 60 साल की उम्र के बाद योजना से जुड़ने वालों को एनपीएस में तीन साल पूरा होने पर सामान्य तरीके से खाता खत्म करने का विकल्प होगा। अगर कोई खाताधारक एनपीएस में 3 साल पूरे हुए बिना ही बाहर निकलना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसे कुल कोष के 80 फीसदी हिस्से से वार्षिक वृत्ति खरीदनी होगी। शेष 20 फीसदी राशि उसे मिल जाएगी। एनपीएस की अवधि में अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो पूरा कोष उसके नामित को मिल जाएगा। पीएफआरडीए के इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा।

बिना इंटरनेट भी भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने खरीद रिटर्न जीएसटीआर–2 जमा कराने के लिए ऑफलाइन सुविधा पेश की है। जीएसटीएन ने कहा कि इस सुविधा से करदाता जीएसटीआर–2 के आंकड़े को एक्सेल में भेज सकेंगे। इससे उन्हें आंकड़ों की खरीद रजिस्टर से तुलना करने में मदद मिलेगी और वे स्वीकार करने, खारिज करने या संशोधन करने जैसे काम भी कर सकेंगे। हम करदाताओं की सुविधा के लिए नए फीचर्स और टूल पेश करना जारी रखेंगे। जीएसटीआर–2 के ऑफलाइन टूल का नया संस्करण पिछले से बेहतर होगा। इसमें करदाताओं को आंकड़ों की खरीद आंकड़ों से तुलना करने में सुविधा होगी।

अभी तक 21 लाख इकाइयों ने जुलाई के लिए जीएसटीआर22 जमा किया है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। करीब 47 लाख इकाइयों ने जीएसटीआर–1 या बिक्री रिटर्न जमा कराया है। इसे साथ–साथ जीएसटीआर–2 या खरीद रिटर्न से मिलाना होगा। इसके अलावा पोर्टल पर जीएसटी सीएमपी–02 को भी सक्रिय किया गया है। इससे करदाताओं को एकमुश्त योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने कंपनियों के लिए एकमुश्त योजना चुनने की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी थी और इसका फायदा 90 फीसदी करदाता उठा सकते हैं।

भारत में बंद नोट दक्षिण अफ्रीका चुनाव में आयेंगे काम

भारत में हुई नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन नोटों का क्या हुआ? बैंक में उन्हें जमा करने के बाद उनका क्या किया गया? अगर नहीं पता, तो हम बताते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बंद किए वे सभी 500 और 1000 के नोट दक्षिण अफ्रीका भेजे जा रहे हैं, जहां उन्हें होने वाले चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा केरल में कन्नूर की कंपनी वेस्टर्न इंडियन प्लाइवुड लिमिटेड के वजह से हो रहा है, जो बीते नवंबर से उन नोटों को हार्ड बोर्ड (लकड़ी के) बनाकर रीसाइकल करने में जुटी है। 2019 में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव होने हैं

और यह हार्ड बोर्ड उसी दौरान काम आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तिरुवनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय दफ्तर से उन्हें तकरीबन 800 टन के बंद किए गए नोट मिले थे। 1945 में इस कंपनी की स्थापना कन्नूर के वलापट्टनम में हुई थी, जो प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड और फ्लश डोर तैयार करती है।

6 से ज्यादा टिकट बुक के लिए आधार जरुरी

इंडियन रेलवे ने आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने की लिमिट बढ़ा दी है। अब IRCTC से एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इससे अपना आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा। यह नियम 26 अक्टूबर से लागू हो गया है। यात्रियों द्वारा आईआरसीटीसी के ऑनलाइन पोर्टल से आधार कार्ड लिंक कराने के लिए रेलवे ने यह नया तरीका निकाला है। साथ ही आईआरसीटीसी ने साफ किया है कि बिना आधार कार्ड लिंक किए यूजर एक महीने में 6 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर यूजर को एक महीने में 6 टिकट से ज्यादा टिकट बुक करनी हैं तो आधार कार्ड से अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को लिंक करना होगा। ❑❑

स्वदेशी महारैली की प्रचार पोस्ट ने फेसबुक पर बचाया धमाल

added 2 new photos.
November 7 at 9:50pm ·

स्वदेशी महारैली में कोष प्रमुख सतपाल जी व सहयोगी प्रीतपाल जी स्वदेशी दानपात्र लेकर खुद ही घूम रहे थे! कोई 10 कोई 20... 50 या 100रुपये पात्र में डाल रहे थे! तभी एक बहुत साधारण वेष में व्यक्ति आगे आया और उसने 1100 रुपये डिब्बे में डाल दिए! प्रीतपाल जी स्तब्ध!! "बाबूजी देश का काम है अच्छे काम में देने से मेरा पैसा घटेगा नहीं बढ़ेगा ही..." शायद वह बिहार या झारखण्ड से था! ऐसे ही लोगों ने 2 घटें में ही 5/450 रुपये पात्र में डाल दिए...यही है स्वदेशी की ताक़त! एक दूसरा प्रसंग हुआ... प्रो: फुलचन्द जी से ही सुनो "हमने एक प्रयोग किया...60एक परिचितों के नाम निकाले उन्हें केवल SMS,mail व फ़ोन किए, कहीं गए नहीं और उन्होंने कोई पौने तीन लाख रुपये जमा करा दिए...अमेरिका में बैठे एक बंधु विश्रुत आर्य जी ने तो केवल Whatsapp संदेश रो ही 70,000रुपये भेज दिए" इरा अभियान की असली ताक़त ही है सामान्य जन की स्वदेशी भक्ति....वन्देऽऽऽमातरम..

added 3 new photos.
November 4 at 8:22pm ·

ब्लूम्बर्ग लिखता है कि एक लाख लोगों कि भीड़ रामलीला मैदान में स्वदेशी jagaran मंच की महारेलि me दिल्ली की सड़कों पर उतरी। आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यक्र समीक्षा हुई aur कार्यकर्ताओं और समाज का धन्यवाद किया गया!

Provide translation to English

Swadeshi Jagaran Manch (officially)
Published by उज्ज्वल वर्मा [?] · October 30 at 3:24pm ·

Press Coverage स्वदेशी महारैली - 29 अक्टूबर 2017 (रविवार)

Provide translation to English

चीनी सामान के बहिष्कार के लिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन वीडियो - हिन्दी न्

चीनी सामान के बहिष्कार के लिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हिन्दी न्यूज

Satish Kumar added 4 new photos — feeling strong with Ashwani Mahajan.
November 6 at 10:59pm ·

स्वदेशी अभियान की एक अदृश्य नायिका: "जाइये वह काम भी तो जरुरी है, रात तक यह ड्रिप व injection पुरे हो जायेंगे, तब तक आप वापिस आ ही जायेंगे फिर घर चलेंगे" हस्पताल के बैड पर गंभीर बीमारी की दवाई(ड्रिप से) लेते हुए नीरू बहिन जी ने पति डॉ.अश्वनी जी को कहा...वे असमंजस में थे क्योंकि कार्यालय पर एक स्वदेशी की आवश्यक बैठक थी नीरू जी की बात सुन कुछ सोचा ,और वे चल पड़े। 7-8 महीने से वे एक कठिन रोग से लड़ रहीं थी,इधर डा: साहेब चीन से लड़ने(स्वदेशी सुरक्षा अभियान)में लगे थे। किन्तु नीरू जी ने महारैली तक अश्वनी जी को रोकने का तो सवाल ही नहीं...हर समय अभियान का काम करते रहने को प्रोत्साहित किया...और वे दिन रात जुटे रहे!...सुसंयोग रैली आते आते उन्होंने रोग पर विजय पा ली,अब ठीक हैं...ईश्वर का धन्यवाद
त्याग इनका भी कम नहीं-- 4 अगस्त को राजस्थान के विचार विभाग प्रमुख जयसिंह शक्तावत जी पर वज्राघात हुआ। उनका एकमात्र 38 वर्षीय पुत्र अचानक बीमार हो चल बसा। पर 5 सितम्बर को मासिक प्रक्रिया पूरी कर स्वदेशी के एक आवश्यक प्रवास पर चल पड़े। दिल्ली रैली में सबको साथ लेकर पहुंचे.... पुरानी कविता याद आरही है...किस रज से बनते कर्मवीर...

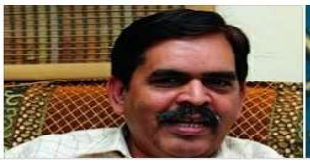

added 2 new photos.
November 1 at 11:06pm ·

"मैं आज बहुत प्रसन्नचित हूँ " अरुण ओझा(राष्ट्रीय संयोजक) ने खिले मुख से जब यह शब्द कहे तो मैं सोचने लगा वास्तव में हर कार्यकर्ता ही तो आज प्रसन्न है! दिल्ली की टीम ने तो जितनी मेहनत की वह अपने आप में प्रेरक है! "स्वदेशी स्वीकार-चायनीज बहिष्कार" के उदघोष से रामलीला मैदान गूँज उठा गत 29 अक्तूबर को! केरल से लेकर जम्मू कश्मीर व अरुणाचल से गुजरात, सारा देश ही चला आया दिल्ली! बिना किसी बड़े नेता या नाम के इतने लोग? स्वदेशी, देशभक्ति व संगठनशक्ति का संगम....बीजिंग तक पहुँचा उदघोष- "भारत माता की जय"

Provide translation to English

Deepak Sharma Sjm
November 8 at 10:33am ·

"बोल विंदास" में स्वदेशी महा रैली।

Provide translation to English

भारतीय हितों की सुरक्षा हेतु दिल्ली में आयोजित स्वदेशी महारैली में किया गया चीनी वस्तुओं के बह

स्वदेशी महारैली

चित्रों की जुबानी